मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र



हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन



E-mail: eksatbulletin@gmail.com | जबलपुर, शुक्रवार 06 नवंबर 2026 | वर्ष-08, अंक-36, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

प्रदेश में 63 हजार 296 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे 5 ग्रीन फील्ड कारीडोर

हर गांव-शहर को सड़कों से जोड़ना हमारा लक्ष्यः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

एक सत बुलेटिन, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सड़कें विकास की वास्तविक जीवन रेखा होती हैं। मध्यप्रदेश का कोई गांव, कस्बा या शहर बेहतर सड़क संपर्क से वंचित न रहे। हर गांव-शहर को बारहमासी सड़कों से जोड़ना ही हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्टेट हाईवे, फोर लेन, सिक्स लेन, 8 लेन और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण के माध्यम से आधुनिक सड़क नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इससे प्रदेश में कनेक्टिविटी का नेटवर्क और मजबूत होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मंडल के संचालक मंडल की 49वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि सड़कों के जो काम निमार्णाधीन हैं, उनमें कार्य की गति बढ़ाकर तेजी से पूरा कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कों का



जाल बिछाना है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, उद्योग और मप्र हाऊसिंग बोर्ड के साथ आपसी तालमेल से काम करें। सड़क निर्माण कार्यों की गति तेज करें, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर भी काम करें तथा सभी संभावनाओं पर एक साथ काम करें। मुख्यमंत्री ने निगम द्वारा प्रस्तावित राजमार्ग निधि का नया नामकरण किया। अब यह निधि 'विकसित मध्यप्रदेश संकल्प पथ' के रूप में जानी जाएगी। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह भी उपस्थित थे।

प्रदेश में 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स के निर्माण की चल रही ठोस तैयारी

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में करीब 63 हजार 296 करोड़ रुपए की लागत से कुल 1398 किमी लंबाई वाले पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर्स तैयार करने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। यह फोर लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर, पेव्हड शेल्डर सहित होंगे। इनमें भोपाल से मंदसौर 258 किमी, सागर से सतना 227 किमी, जबलपुर से आशापुर 358 किमी, भोपाल से ग्वालियर 320 किमी तथा कटनी से सिंगरौली 235 किमी शामिल हैं। बताया गया कि भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना एवं जबलपुर- आशापुर में डीपीआर कंसलटेन्ट द्वारा फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कंसलटेन्ट द्वारा विभिन्न अलाईनमेंट विकल्प दिए गए हैं। एमपीआरडीसी द्वारा श्रेष्ठ अलाईनमेंट का चयन करने की प्रक्रिया प्रगति में हैं। इसी तरह भोपाल-ग्वालियर एवं कटनी-सिंगरौली में डीपीआर कंसलटेन्ट का चयन करने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है। संचालक मंडल द्वारा इन पांचों ग्रीनफील्ड कॉरीडोर्स की फीजिबिलिटी रिपोर्ट तथा फीजिबल पाए जाने पर इनकी डीपीआर तैयार करने की अनुमति मप्र सड़क विकास निगम को दी गई।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय कुमार दुबे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग श्री सुखवीर सिंह, प्रमुख सचिव वन श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सचिव जनसम्पर्क एवं मप्र रोड डेव्हलपमेंट कापोर्रेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री भरत यादव, मप्र सड़क विकास निगम लिमिटेड के स्वतंत्र संचालक श्री वेंकटेश बालासुब्रमानियम, निगम के दूसरे स्वतंत्र संचालक श्री धमार्नंद सारंगी सहित अन्य सदस्यगण भी उपस्थित थे।

पुरानी दिल्ली इलाके में एक इमारत ढही, दो की मौत

एजेन्सी, नई दिल्ली



दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में बृहस्पतिवार सुबह एक इमारत का हिस्सा ढहने से दो लोगों की मौत हो गई और कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। चावड़ी बाजार इलाके की गली शहतारा में इस इमारत में कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा था ।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, उसे सुबह करीब 9:50 बजे इमारत ढहने की सूचना मिली। इसके बाद दमकल की छह गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं।

इस हादसे ने दिल्ली के पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों में इमारतों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इन इलाकों की संकरी गलियों के कारण आपातकालीन सेवाओं को मौके तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। दो महीने से भी कम समय में दिल्ली में इमारत ढहने की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले छह सितंबर को दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पेइंग गेस्ट आवास वाली पांच मंजिला इमारत ढह गई थी। उस हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी और छह अन्य घायल हुए थे।

सरकारी ताकत इस्तेमाल कर परिवार को अमीर बनाने का आरोप

ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष

एजेन्सी, वॉशिंगटन डीसी

मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद अब राष्ट्रपति ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके जरिए उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यूज एजेंसी अढ के मुताबिक डेमोक्रेट्स आरोप लगा रहे हैं कि ट्रम्प ने अपने पद का इस्तेमाल कर अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया और संपत्ति जुटाई। इससे आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। डेमोक्रेटिक सांसद रॉबर्ट गार्सिया ने कहा है कि वे यह पता लगाएंगे राष्ट्रपति रहते हुए ट्रम्प और उनके परिवार की संपत्ति कैसे बढ़ी। उनका फोकस ट्रम्प



के बेटों और दामाद जेरेड कुशनर के कारोबारी सौदों पर है। गार्सिया ने जांच के लिए पांच मुद्दे तय किए हैं। इनमें ट्रम्प परिवार के कारोबारी सौदे, जेफ्री एपस्टीन मामले की जांच में ट्रम्प प्रशासन की भूमिका और अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी की छापेमारी और कार्रवाई शामिल हैं।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स- हाउस में कुल 435 सीटें हैं। सभी सीटों पर चुनाव हुए। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने 242 और ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी ने 151 सीटें जीती हैं। 42 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। डेमोक्रेट्स को जरूरी बहुमत मिल चुका है।

सीनेट- सीनेट की 100 सीटों में से 35 पर चुनाव हुए हैं। अब तक 33 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें डेमोक्रेटिक पार्टी ने 20 और रिपब्लिकन पार्टी ने 13 सीटें जीती हैं। बाकी 2 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। इन नतीजों को मिलाकर डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 54 और रिपब्लिकन पार्टी के पास 44 सीटें हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताई बड़ी उपलब्धि

डीआरडीओः भारत ने स्वदेशी 'प्रलय' मिसाइल का सफल परीक्षण किया



एजेन्सी, नई दिल्ली

भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली 'प्रलय' मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी।

राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि डीआरडीओ ने गुरुवार सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर ओडिशा के तट के पास स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह परीक्षण यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल के तहत किया गया। मिसाइल ने निर्धारित सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। विभिन्न रेंज उपकरणों के जरिए जुटाए गए आंकड़ों से इसकी सफलता की पुष्टि हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इससे पहले पिछले महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम का सफल उड़ान परीक्षण किया था। इस परीक्षण के दौरान सिस्टम ने 21 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की और लंबे समय तक समताप मंडल (स्ट्रैटोस्फियर) में उड़ान भरने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था।

संबित पात्रा का राहुल गांधी पर तंज

'संसद में 5-6 मिनट भी नहीं बैठ पाते, बहस क्या करेंगे': विपक्ष पर उठाए सवाल

एजेन्सी, नई दिल्ली

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुली बहस की चुनौती पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संसद में बहस करनी चाहिए, न कि सड़कों पर। उन्होंने सवाल किया कि नेताओं के बीच बहस सड़कों पर होनी चाहिए या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में?

'बहस संसद में होनी चाहिए सड़कों पर नहीं'

पात्रा ने कहा, 'राहुल गांधी कल प्रधानमंत्री के साथ बहस करना चाहते थे। एक तरफ प्रधानमंत्री बैठे होंगे और दूसरी तरफ वह खुद बैठेंगे। राहुल गांधी के पास किसी भी मुद्दे पर कोई आंकड़ा नहीं होता। उन्हें देश में चल रही ज्यादातर मुद्दों की जानकारी भी नहीं है। लेकिन



जहां तक अव्यवस्था फैलाने की बात है, उसमें वह सबसे आगे हैं। नेताओं के बीच बहस सड़कों पर होनी चाहिए या लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में?'

उन्होंने आगे कहा, 'लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी में संसद में लगातार पांच-छह मिनट से ज्यादा बैठने का धैर्य नहीं है। जो व्यक्ति संसद में लगातार पांच-छह मिनट नहीं बैठ सकता, वह वहां बहस भी नहीं करना चाहेगा। वह संसद में बहस करने के बजाय सड़क पर झगड़ा करना पसंद करेगा।'

'इंडी गठबंधन में एकजुटता है या नहीं, इस पर हो बहस'

एक अन्य बयान में संबित पात्रा ने विपक्षी गठबंधन इंडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाल ही में गठबंधन के सभी नेता रामलीला मैदान में जुटे थे। उन्होंने दावा किया था कि वहां 10 लाख लोग आएंगे, लेकिन वास्तव में 20 हजार से ज्यादा लोग नहीं पहुंचे। पात्रा ने कहा, 'यह पूरे इंडी गठबंधन की कुल ताकत है। मेरी राहुल गांधी को सलाह है कि अगर आप बहस करना चाहते हैं तो अपने तथाकथित गठबंधन सहयोगी से बहस कीजिए। आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आपके दोस्त हैं और इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन कल आप ही कह रहे थे कि अगर सबसे भ्रष्ट सरकार कोई है तो वह पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है।'

पाकिस्तानी सेना की कायराना हरकत

पीओजेके में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बरसाईं गोलियां, पांच की मौत

एजेन्सी, नई दिल्ली

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में जारी आंदोलन एक बार फिर हिंसक टकराव में बदल गया है। जम्मू संभाग के पुंछ जिले से सटे रावलाकोट में वीरवार तड़के करीब 5:00 बजे पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के कार्यकताओं को मुख्य बस टर्मिनल से हटाने के दौरान फायरिंग शुरू कर दी। इसमें पांच कार्यकताओं की मौत हो गई। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। करीब दो घंटे तक गोलीबारी और झड़प चलती रही। इसे लेकर शहर के दूसरे हिस्सों में तनाव बढ़ गया है।

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तानी सेना वीरवार तड़के



रावलाकोट के मुख्य बस टर्मिनल पहुंची, जहां जेएएसी कार्यकर्ता करीब पांच महीने से धरने पर बैठे थे। सेना ने धरना स्थल पर लगाए गए अवरोध हटाने शुरू किए। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच टकराव शुरू हो गया। इसी बीच सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। शाम करीब 5:00 बजे सेना ने धरना स्थल को खाली कराकर बस टर्मिनल को नियंत्रण में लेने का दावा किया है।

प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने पत्रकार-वार्ता को किया संबोधित

13 करोड़ नाम काटने का झूठा आंकड़ा बताकर जनता को भ्रमित कर रहे राहुल गांधी : खण्डेलवाल

राहुल गांधी कांग्रेस की चुनावी हार का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ रहे हैं : प्रेम शुक्ला

एक सत बुलेटिन, भोपाल

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रेम शुक्ला ने गुरूवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देशभर में अराजकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। एसआईआर नई प्रक्रिया नहीं है। देश के आजाद होने के बाद एसआईआर की प्रक्रिया 12 बार हो चुकी है, जिनमें 10 बार यह प्रक्रिया कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। राहुल गांधी मतदाता सूची से 13 करोड़ लोगों के नाम काटने का झूठा व गलत आंकड़ा देश की जनता को बताकर भ्रमित करने



का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। वह विदेशी नागरिकों और घुसपैठियों को मतदाता बनाए रखने के लिए देश में अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रेम शुक्ला ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विमर्श के लिए हमारे संविधान में संसद का सदन निर्धारित किया है। राहुल गांधी सदन में बहस करने की बजाय हंगामा खड़ा करते हैं। सदन छोड़कर भागने वाले राहुल गांधी सड़क पर बहस की चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी को सड़क पर बहस की चुनौती देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। चार बार ऐसा मौका आया, जब बहस के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जब सदन में अपना पक्ष रखने लगी तब राहुल गांधी और कांग्रेस सदन छोड़कर चले गए। रामलीला में राहुल लीला करने वाले लोग देश में अराजकता फैलाने का कुत्सित षड्यंत्र कर रहे हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि मतदाता सूची से 13 करोड़ लोगों के नाम काटे जाने का दावा भ्रामक है। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और अन्य श्रेणियों के मतदाताओं के सत्यापन को राहुल गांधी और विपक्षी दलों के नेता गलत तरीके से प्रस्तुत कर देश में भ्रम फैला रहे है। राहुल गांधी और विपक्षी दलों के नेता एसआईआर के तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने की बजाय संवैधानिक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। देश की लोकतांत्रिक ताकतें और संवैधानिक मजबूत रहेंगी, तभी देश मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के कई राजनीतिक दल और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की मंशा रखने वाली ताकतें सक्रिय हैं। विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर देश में अराजकता और भ्रम का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष की इस नकारात्मक राजनीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ह्यलोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओह्व अभियान शुरू किया है, जिसे मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले तक पहुंचाया जाएगा। अभी इंदौर, जबलपुर और भोपाल में बड़ी पदयात्राएं निकाली गई हैं। आने वाले दिनों में जिलों में भी पदयात्राएं निकाली जाएंगी। इंदौर, जबलपुर और भोपाल की पदयात्राओं में समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता इस अभियान को मिल रहे जनसमर्थन का प्रमाण है।

फाइनल कॉम्पिटीशन में हरिओम जटिया ने विजेताओं को किया सम्मानित

गरिमा मिस और खुशबू मिसेज कैटेगरी में बनी मिस एंड मिसेज मध्य प्रदेश सीजन-4 की विजेता

एक सत बुलेटिन, भोपाल

फैशन, ग्लैमर, आत्मविश्वास और नारी शक्ति के खूबसूरत संगम के बीच मिस एंड मिसेज मध्य प्रदेश सीजन-4 का भव्य ग्रैंड फिनाले ताज लेकफ्रंट होटल में आयोजित किया गया। द पेजेंट इंडिया कंपनी की ओर से आयोजित इस कॉम्पिटीशन में मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से आईं करीब 50 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया। रैंप पर आकर्षक अंदाज, स्टाइलिश प्रस्तुतियों और खूबसूरत परिधानों ने शाम को फैशन के रंगों से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिलीप सूर्यवंशी और विशिष्ट अतिथि सेलिब्रिटी प्रमोटर, एक्सीलेंसी टाइम्स एंटरटेन्मेंट के प्रबंध संचालक हरिओम जाटिया उपस्थित हुए। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। जूरी पैनल में अमानत सिंह चौहान सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल रहीं। वहीं, क्लॉडिया सेसला और चांदनी भगवानी ने सेलिब्रिटी जूरी के रूप में सहभागिता की।



प्रतियोगिता गरिमा गोस्वामी ने अपनी प्रतिभा और प्रभावशाली प्रस्तुति के दम पर मिस मध्य प्रदेश का ताज अपने नाम किया। वहीं, मिसेज कैटेगरी में खुशबू गुप्ता मिसेज मध्य प्रदेश सिल्वर विनर और आकांक्षा जैसवाल मिसेज मध्य प्रदेश गोल्ड विनर बनीं। विजेताओं की क्राउनिंग के दौरान दर्शकों ने तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय पेजेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित क्वीन अनिका चक्रवर्ती, सिमरन पांडे, प्रियंका जोशी और अश्विनी वागद्रे की विशेष क्राउनिंग भी की गई।



सपनों को दी नई उड़ान

शो की संयोजक फरहा अनवर ने कहा कि इस सीजन में बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों और गांवों की महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भागीदारी की। करीब 50 प्रतिभागियों की मौजूदगी यह दशार्ती है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं अब अपने सपनों को नई उड़ान देने और अपनी पहचान राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने के लिए आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मंच महिलाओं को अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखारने का अवसर प्रदान करते हैं।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वार्ड 46 में हुआ पौधारोपण, जनप्रतिनिधियों ने दिया योगदान

एक सत बुलेटिन, भोपाल

वार्ड 46 में नूतन कॉलेज के सामने नर्मदा मिशन के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। इस आयोजन में नगर के विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से योगदान प्रदान करते हुए आयोजन को सफल बनाया।

कार्यक्रम में योगेंद्र सिंह चौहान (पार्षद, वार्ड 46) द्वारा इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई और नूतन कॉलेज के सामने आयोजित विशेष कार्यक्रम में अपनी माताजी श्रीमती शीला देवी जी की स्मृति/सम्मान में पौधा लगाकर योगदान दिया। वहीं पी.सी. शर्मा (पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन) द्वारा कार्यक्रम में विशेष सहभागिता करते हुए उन्होंने अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती द्वारिका शर्मा जी एवं दादी स्वर्गीय श्रीमती चंदू बाई जी के नाम पर देव वृक्ष रोपित किए। यह पौधारोपण कजलियों के पावन हरित पर्व के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसमें मिशन के 108 दिनों के संकल्प के तहत एक ही दिन में 131 पौधों का रोपण किया गया।



दीपावली के लिए कंपनी ने किए विशेष इंतजाम

दीपावली के लिए मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा हर घर, दुकान, प्रतिष्ठान एवं व्यापारिक केन्द्रों की रोशनी के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के कमिश्नरी जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थाई शिकायत निवारण केन्द्र खोले हैं। वहीं भोपाल शहर में शिकायत निवारण के लिए लगभग 1,880 कार्मिकों की ड्यूटी चौबीसों घंटे शिकायत निवारण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई हैं। यह टीमें एफओसी वाहन, सुरक्षा उपकरणों और आवश्यक विद्युत सामग्री/उपकरणों के साथ तीन शिफ्टों में उपभोक्ता शिकायतों का निराकरण करने के साथ ही निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी।

ड्रग्स और अवैध शराब की बिक्री, परिवहन, निर्माण पर करें कठोर कार्रवाई : संभागायुक्त

एक सत बुलेटिन, भोपाल

संभाग आयुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि संभाग के सभी जिलों में ड्रग्स और अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन आदि के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाकर ऐसा करने वालों के खिलाफ रा.सु.का, एन.डी.पी.एस एक्ट आदि के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाए, इनका नेटवर्क ध्वस्त किया जाए। साथ ही नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस कार्य में थोड़ी भी लापरवाही अथवा कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्ण अर्न्तविभागीय समन्वय और अर्न्तजिला समन्वय के साथ भोपाल संभाग को ड्रग्स मुक्त और अवैध शराब मुक्त किया जाए।

संभागायुक्त श्री कर्मवीर शर्मा ने इस संबंध में गुरूवार को संभागायुक्त कार्यालय में विभाग के सभी जिलों की अर्न्तविभागीय समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में वीसी के माध्यम से भोपाल पुलिस कमिश्नर श्री संजय कुमार, आईजी भोपाल देहात श्री पंकज पाण्डे, आईजी नर्मदापुरम श्री चंद्रशेखर सोलंकी, संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, आबकारी अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि संभाग के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और छात्रावासों में एन्टी ड्रग्स समितियां बनाई जाएं, जो नियमित बैठकें करें और ड्रग्स के उपयोग के विरूद्ध विद्यार्थियों को जागरूक करें। साथ ही ड्रग्स, अवैध शराब की बिक्री, परिवहन आदि की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराएं।

संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि ड्रग्स के उन्मूलन के लिए जिलेवार कार्य योजना बनाएं और उस पर अमल किया जाए। प्रत्येक छात्रावास के लिए एक नोडल अधिकारी बनाया जाए जो ड्रग्स के विरूद्ध निरंतर कार्रवाई करें। साथ ही पुलिस प्रशासन, आबकारी अधिकारी आदि का संयुक्त दल विद्यालयों, छात्रावासों और अन्य स्थलों का निरंतर भ्रमण कर ड्रग्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

भोपाल में आईएफएमआईएस केयर्स थीम पर दो दिवसीय प्रशिक्षण हुआ आयोजित

जिला कोषालय भोपाल ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को दी वित्तीय कार्यों की जानकारी





एक सत बुलेटिन, भोपाल

प्रदेश में वित्तीय कार्य को अधिक पारदर्शी, आसान और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आईएफएमआईएस केयर्स IFMIS Cares' थीम के तहत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला कोषालय भोपाल द्वारा आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री राहुल सिंह, श्री अतुल सिंह और श्रीमती कुलवंती खलखो ने अधिकारियों को IFMIS की कार्यप्रणाली और विभिन्न मॉड्यूल की विस्तार से जानकारी दी।

प्रशिक्षण में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की नियुक्ति, उनके अधिकारों, अधिकारी शक्ति पुस्तिका, कोषालय संहिता और अन्य जरूरी नियमों के बारे में बताया गया। इसके साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारियों, बिल प्रस्तुत करते समय रखी जाने वाली सावधानियों और IFMIS पोर्टल की DDO स्क्रीन व रिपोर्टों के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई।

तकनीकी समस्याओं का हुआ समाधान

कार्यक्रम में बिल प्रस्तुत करते समय होने वाली सामान्य गलतियों से बचने के उपाय बताए गए। 'IFMIS Cares Camp' के तहत स्थानीय स्तर पर आने वाली तकनीकी समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई, जिससे वित्तीय कार्य बिना किसी गलती के और तेजी से पूरे हो सकें।

बीना-रुठियाई रेलखंड पर पगारा से रूठियाई 25 हजार वोल्ट की ओवरहेड विद्युत लाइन चालू



एक सत बुलेटिन, भोपाल

पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल द्वारा रेल विद्युतीकरण कार्य के अंतर्गत बीना-रुठियाई रेलखंड के पगारा से रूठियाई हिस्सों में 25,000 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसी ओवरहेड विद्युत लाइन को दिनांक 05 नवंबर 2026 से ऊर्जीकृत (चालू) किया जा रहा है। पगारा से रूठियाई रेलखंड की ओवरहेड विद्युत लाइन हर समय चालू मानी जाएगी। इस विद्युत लाइन में अत्यधिक उच्च वोल्टेज प्रवाहित होगा, जिससे संपर्क में आने अथवा नजदीक जाने पर जानलेवा दुर्घटना हो सकती है।

अतः सभी रेल उपयोगकताओं, आम नागरिकों एवं संबंधित क्षेत्र के निवासियों से अपील है कि वे विद्युत लाइन के समीप न जाएं, उसके नीचे किसी प्रकार का कार्य न करें तथा रेलवे ट्रैक एवं परिसर में अनधिकृत प्रवेश से बचें।

रेलवे प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि अपनी सुरक्षा के लिए विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।

धूल नियंत्रण के लिए नियमित पानी का छिड़काव व स्वीपिंग पर निगमायुक्त का विशेष जोर

प्रदूषण फैलाने और खुले में कचरा जलाने वालों पर होगी सख्त चालानी कार्रवाई: निगमायुक्त

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



शहर की आबोहवा को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा एक समग्र एवं प्रभावी पहल की जा रही है। शीतकालीन मौसम के दौरान वायु गुणवत्ता को उत्कृष्ट स्तर पर बनाए रखने के लिए निगमायुक्त अग्रिम कुमार द्वारा स्मार्ट सिटी कार्यालय में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी सर्दियों को ध्यान में रखते हुए 100 दिवसीय विशेष विंटर एक्शन प्लान तैयार कर उसे जमीनी स्तर पर मुस्तैदी से लागू करने के निर्देश दिए गए। निगमायुक्त कुमार ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि शहर में पी.एम. 10 एवं पी.एम. 2.5 के स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर बनाए रखना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए शहर भर में वायु गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के स्पष्ट लक्ष्य तय कर दैनिक व साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। धूल नियंत्रण व निर्माण स्थलों की निगरानी पर विशेष बल बैठक में उन्होंने बताया कि कार्ययोजना के अंतर्गत धूल प्रदूषण को रोकने के लिए प्रमुख मार्गों पर आधुनिक मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों का उपयोग और वाटर स्प्रिंकलर के जरिए नियमित जल छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ ही सड़कों, फुटपाथों तथा निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित कराया जा रहा है, ताकि उड़ने वाली धूल से आम नागरिकों को राहत मिल सके। नियमों के उल्लंघन पर की जायेगी सख्त कार्रवाई शहर के सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने एवं प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए निगमायुक्त ने फील्ड अमले को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सड़कों व फुटपाथों पर मलबा फेंकने, सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और खुले में कचरा या अन्य अपशिष्ट जलाने वालों के विरुद्ध सख्त चालानी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। फील्ड अधिकारियों को कार्रवाई के स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर नियमित समीक्षा करने को कहा गया है। वायु प्रदूषण के अन्य स्रोतों को नियंत्रित करने के क्रम में होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को लकड़ी व कोयले के तंदूर के स्थान पर एलपीजी या इलेक्ट्रिक तंदूर अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और सतत निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं आरटीओ के समन्वय से वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्रों की सघन जांच की जाएगी तथा कृषि क्षेत्रों में नरवाई जलाने की घटनाओं पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस 100 दिवसीय सघन अभियान के माध्यम से नगर निगम का लक्ष्य शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण और शुद्ध वायु उपलब्ध कराना है।

दीपावली एवं छठ पर शहर में स्वच्छता, प्रकाश, साज सज्जा और सुरक्षा के होंगे बेहतर इंतजाम : महापौर

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



रोशनी के पावन पर्व दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर संस्कारधानी जबलपुर में उत्सव का उल्लास और भव्यता बढ़ाने नगर निगम ने व्यापक तैयारियां की हैं। शहरवासियों को स्वच्छ, सुंदर, रोशन और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सफाई, प्रकाश, विद्युत साज-सज्जा, पेयजल, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। महापौर जगत बहादुर सिंह ''अन्नू'' ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि दीपावली एवं छठ महापर्व के दौरान नागरिकों और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी व्यवस्थाएं बेहतर, व्यवस्थित और चाक-चैबंद रहें। महापौर एवं निगमायुक्त अग्रिम कुमार के निर्देशानुसार सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। छठ महापर्व के अवसर पर शहर के 27 प्रमुख घाटों एवं पूजा स्थलों पर नगर निगम द्वारा विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इनमें गौरीघाट, तिलवाराघाट, हनुमानताल, अधारताल, मानेगांव, कालीघाट, महाराजपुर एवं गोकलपुर सहित अन्य प्रमुख पूजा स्थल शामिल हैं। इन सभी स्थलों पर व्रतधारियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, मोबाइल टॉयलेट, पेयजल टैंकर तथा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जा रही है। घाटों एवं आसपास के क्षेत्रों में मच्छरों से बचाव के लिए नियमित फॉगिंग भी कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए एम्बुलेंस, कंट्रोल रूम, नाव एवं प्रशिक्षित बचाव दल की व्यवस्था भी रहेगी। श्रद्धालुओं को सुरक्षा संबंधी सावधानियों की जानकारी देने के लिए घाटों पर नियमित अनाउंसमेंट एवं प्रचार-प्रसार भी कराया जाएगा। पटाखा बाजारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दीपावली के दौरान नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी पटाखा बाजारों के आसपास विशेष अग्निशमन व्यवस्था की गई है। संभावित अग्नि दुर्घटनाओं पर तत्काल नियंत्रण पाने के लिए अलग से फायर सेफ्टी वाहन एवं पानी के टैंकर तैनात किए गए हैं। आवश्यकतानुसार फायर सेफ्टी टीम, बचाव दल एवं अन्य संसाधनों को भी सक्रिय रखा जाएगा, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके। नगर निगम का उद्देश्य है कि नागरिक सुरक्षित वातावरण में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना सकें। त्योहारों के दौरान शहर की स्वच्छता को विशेष प्राथमिकता देते हुए महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू की अगुवाई में धनतेरस एवं दीपावली की रात 4 बजे से शहरभर में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया जाएगा।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर दर्ज करने की मांग, राष्ट्रीय यादव महासभा ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सार्वजनिक मंच से आराध्य भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में की गई कथित अपमानजनक एवं आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में आज दिनांक 05 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय यादव महासभा जबलपुर के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक, जबलपुर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल स्वतः दर्ज करने एवं कठोर वैधानिक कार्रवाई की मांग की। महासभा ने ज्ञापन में कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान श्रीकृष्ण के संबंध में की गई कथित टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। भगवान श्रीकृष्ण केवल यादव समाज ही नहीं, बल्कि देश-दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं के आराध्य हैं। उनका जीवन दर्शन, गीता का उपदेश और भारतीय संस्कृति में उनका योगदान संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। ऐसे आराध्य के प्रति सार्वजनिक मंच से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है।ज्ञापन सौंपने के अवसर पर प्रमुख रूप से शिव यादव, रामरतन यादव, सुभाष यादव, एडवोकेट प्रभात यादव, शशांक यादव, एडवोकेट राजकुमार यादव, घनश्याम यादव, विजय सिंह यादव, प्रदीप यादव (पूर्व पार्षद), पवन यादव, एडवोकेट दुर्गा यादव, रामकिशन यादव, डॉ. एच.आर. यादव, जितेन्द्र यादव सहित अनेक सामाजिक साथी उपस्थित रहे।

पराली जलाने पर लगी रोक हटाने की मांग, अन्नदाताओं ने मांग को लेकर पुराना बस स्टैंड में किया धरना प्रदर्शन

एक सत बुलेटिन, सिहोरा



खरीफ की प्रमुख फसल धान की कटाई के बाद अवशेष पराली का निस्तारण उसको जालना प्राकृतिक काम है इस काम को अन्नदाता कई वर्षों से करते आ रहे हैं अब जबलपुर जिला प्रशासन में अन्नदाता के पराली निस्तारण के काम में रोक लगाने और पराली जलने पर अन्नदाता के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने पर अन्नदाताओं में जबरदस्त आक्रोश बन गया गुरुवार को आक्रोशित अन्नदाताओं ने पराली जलाने पर शासन के आदेश के खिलाफ रैली निकाली और पुराना बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर शासन के आदेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की दोपहर 1 से देर शाम 7 बजे तक चले धरना प्रदर्शन में एक हजार से अधिक अन्नदाता शामिल थे अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के संयोजन में हुए विरोध प्रदर्शन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार कुर्मी के संयोजन में हुए विरोध प्रदर्शन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट इंद्र कुमार पटेल जिला पंचायत सदस्य प्रदीप पटेल छोटे पटेल ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष संत कुमार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बिहारी पटेल किसान यूनियन जिला अध्यक्ष रमेश पटेल भारत कृषक समाज तहसील अध्यक्ष रामगोपाल पटेल पूर्व जनपद सदस्य सत्यवती के के पटेल सरपंच बहादुर पटेल विनय पटेल शांति रामराज पटेल अजीत पटेल रंजीत पटेल राजेश यादव दीपक यादव सुनील विश्वकर्मा उमेश पटेल संदीप पटेल विवेक पटेल डॉक्टर संतोष पटेल संतोष राय दीपक पटेल के साथ बड़ी संख्या में अन्नदाता शामिल थे।धरना प्रदर्शन के बाद आक्रोशित अन्नदाताओं ने प्रदेश शासन के मुखिया मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम ज्योति परस्ते को ज्ञापन सौंपा।

रोजाना हजार रजिस्ट्रियों का लक्ष्य, हर पटवारी को 20 का टारगेट

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन ने अब रोजाना एक हजार रजिस्ट्रियों का लक्ष्य तय किया है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने गुरुवार सुबह योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रत्येक पटवारी को प्रतिदिन कम से कम 20 रजिस्ट्रियां कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना है।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन पटवारियों ने अपने हलके में रजिस्ट्री का काम पूरा कर लिया है, उन्हें दूसरे क्षेत्र में भेजने के बजाय उनके अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे अन्य पटवारियों को भी बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने सर्वर की गति अनुकूल रहने पर रजिस्ट्री के काम को प्राथमिकता देने को कहा, ताकि उपलब्ध समय का अधिकतम उपयोग किया जा सके। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर भी सख्ती... बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लें और केवल औपचारिक कार्रवाई के बजाय उनका समाधान सुनिश्चित करें। सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश भी दिए गए।

धनतेरस के लिये दुल्हन की तरह सजे बाजार आज बाजारों में होगी जमकर खरीददारी

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



दीपोत्सव पर्व की शुरूआत शुक्रवार को धनतेरस के साथ हो रही दीपोत्सव पर्व की तैयारियों को लेकर पिछले महीने भर से लोग व्यस्त रहे। घर-मकान, प्रतिष्ठान की सफाई पुताई करने के बाद अब लोग त्यौहार मनाने के मूड में आ गये। बाजारों में धनतेरस के लिये सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। दो दिन पूर्व से बाजार रंग बिरंगी रोशनी और माल के नये-नये स्टॉक, उपहार योजना, डिस्काउंट व उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाली योजनाओं के साथ सजधज गये। धनतेरस पर जमकर बाजारों में धन बरसेगा, लोग अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीददारी करेंगे। शासकीय दफ्तरों में वेतन बट चुका है, केन्द्रीय कर्मचारियों को बोनस की बड़ी-बड़ी रकम मिल चुकी है। लिहाजा बाजार में आज मंहगाई के बावजूद अच्छी बिकवाली होने की उम्मीद है। स्वर्ण आभूषणों से लेकर बर्तन, कपड़े, मेवा मिष्ठान, पकवान, पटाखे, रंगोली और रंग बिरंगी विद्युत झालरों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटम की दुकानों में कुछ ज्यादा ही चमक दमक दिखाई देगी। 6 दिवसीय दीपोत्सव के पहले दिन लोग शुभ मुहूर्त में खरीदी करने के बाद घरों में स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी भगवान की पूजा अर्चना कर पूरे परिवार की स्वस्थ रहने की कामना करेंगे। इसके अलावा दूसरे दिन नरक चौदस का पर्व मनाया जायेगा। इस दिन घूरे में भी और घर के निस्तारी कोनों-कोनों में भी दिये की रोशनी का उजाला किया जायेगा।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अधिवक्ताओं का प्रदर्शन

जबलपुर। अधिवक्ता रोबिन जैन पर हुए प्राणघातक हमले के मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले में शीघ्र एवं प्रभावी कार्रवाई करने तथा हमले में शामिल सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की।

पराली जलाने पर कार्रवाई हुई तो किसान करेंगे तीखा विरोध, अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने की कलेक्टर से की शिकायत

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



जिले के कृषक प्रतिनिधियों ने नवागत कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा से सौजन्य भेंट कर उनका स्वागत किया और किसानों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान प्रमुख रूप से पराली और नरवाई प्रबंधन का मुद्दा उठाया गया। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि खेत खाली होने के बाद रबी की फसल की बुआई के लिए किसानों को महज एक सप्ताह का समय मिलता है। ऐसे में पराली और नरवाई के निस्तारण के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों के सामने इसे जलाने की मजबूरी बन जाती है। कृषक प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि जब तक पराली प्रबंधन के लिए पर्याप्त संसाधन और व्यावहारिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक किसानों पर नरवाई जलाने के नाम पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति में किसानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका तीव्र विरोध किया जाएगा। बैठक में किसानों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई। प्रतिनिधियों का कहना था कि अधिकांश अधिकारी किसानों के फोन तक नहीं उठाते और न ही व्हाट्सएप संदेशों का जवाब देते हैं। इससे किसानों को अपनी समस्याएं और शिकायतें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में परेशानी होती है। उन्होंने कलेक्टर से अधिकारियों को किसानों के फोन उठाने और उनके संदेशों का जवाब देने के संबंध में सख्त निर्देश जारी करने की मांग की।

मां की बगिया में फलदार पौधों की देखरेख के निर्देश...

विकास कार्यों से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर

एक सत बुलेटिन, जबलपुर



कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने गुरुवार को कुंडम क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों, शासकीय योजनाओं और जनसुविधाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत बीजापुरी में विकास एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, वहीं आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक शाला, मां की बगिया और उचित मूल्य दुकान पहुंचकर व्यवस्थाएं देखीं। इसके अलावा कुंडेश्वर धाम स्थित सांदीपनि विद्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत बीजापुरी के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने डिमांड रजिस्टर, मस्टर रोल, पेमेंट बुक सहित अन्य जरूरी अभिलेखों के संधारण की जानकारी ली। उन्होंने पंचायत सचिवों को सभी अभिलेखों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी रखने के निर्देश दिए। वीबी-जी राम जी योजना के तहत जल संरक्षण के लिए बनाए जा रहे लघु तालाबों और मेड़ बंधान के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में पानी के पर्याप्त संचयन और किसानों को सिंचाई के लिए मिलने वाले लाभ का विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को दिए जा रहे पोषण आहार और संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को खेल-खेल में गिनती, हिंदी के अक्षर एवं शब्द और अंग्रेजी की बुनियादी जानकारी दी जाए। इसके बाद शासकीय प्राथमिक शाला बीजापुरी पहुंचकर विद्यार्थियों से पढ़ाई के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बच्चों से गणित के जोड़ के सवाल हल करवाए और इकाई-दहाई के आधार पर संख्याओं को जोड़ने की विधि समझी। शिक्षकों को निर्देश दिए कि बच्चों को गणित की मूल अवधारणाएं सरल तरीके से समझाएं, ताकि वे स्वयं सवाल हल कर सकें। प्राथमिक शाला परिसर में कलेक्टर ने लक्ष्मी स्व-सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर उन्हें मिलने वाले राशन और मध्यान्ह भोजन की स्थिति जानी। उन्होंने राशन वितरण में आने वाली समस्याओं के बारे में भी पूछा और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। ग्राम बीजापुरी में विकसित की जा रही मां की बगिया का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने लगाए गए फलदार पौधों की किस्म, संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली।

संपादकीय

क्या एसआईआर बेमानी है?

अंततः चुनाव आयोग को लौट कर उसी बिंदु पर आना पड़ा, जहां से उसने मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू किया था। अब चुनाव आयोग ने राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) को लिखित निर्देश दिए हैं कि पुराने मतदाता भी फॉर्म 6 भर सकते हैं और इस तरह अधिकृत मतदाता बन सकते हैं। जिनके नाम मतदाता सूची में थे और एसआईआर के दौरान हटा दिए गए, वे मतदाता फॉर्म 6 के जरिए नया आवेदन कर मतदाता बन सकते हैं। एसआईआर के दौरान यह व्यवस्था नहीं थी, बल्कि चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 के साथ एक हलफनामा भी जोड़ दिया था, जिसमें घोषणा करना अनिवार्य तय किया गया था कि वह पहली बार मतदाता बनने के लिए आवेदन कर रहा है।

उस हलफनामे में माता-पिता, दादा-दादी आदि के मतदाता होने की भी घोषणा करनी पड़ती थी। यह मामला अब सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन है, लेकिन चुनाव आयोग को बुद्धू की तरह लौट कर घर आना पड़ा है। अब कोई भी फॉर्म 6 भर कर मतदाता बन सकता है। देश के जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 31 के तहत ऐसा करना दंडनीय अपराध है। यदि पुराना मतदाता फॉर्म 6 के जरिए आवेदन करता है, तो उसे एक साल जेल की सजा तक हो सकती है। लेकिन सर्वोच्च अदालत में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली न्यायिक पीठ ने व्यवस्था दी थी कि जिनके नाम छूट गए हैं या गायब हैं अथवा काट दिए गए हैं, वे फॉर्म 6 के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही उन्हें सजा होगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इसी आशय की बात कही थी। सवाल है कि क्या अदालतें संसद द्वारा पारित और स्थापित कानून के खिलाफ भी व्यवस्था अथवा फैसला दे सकती हैं? सर्वोच्च अदालत की न्यायिक पीठ ने ही आयोग से कडक सवाल पूछा था कि पुराने मतदाताओं से फॉर्म 6 क्यों भरवाया जा रहा है? उनसे फॉर्म 8 के जरिए आवेदन लिए जाएं और स्वीकार किए जाएं। इस न्यायिक विरोधाभास को क्या समझा जाए? अहम सवाल तो यह है कि क्या एसआईआर का संपूर्ण अभियान ही बेमानी साबित हुआ?

दरअसल अब चुनाव आयोग का कहना है कि यदि पुराने, छूटे हुए मतदाता भी फॉर्म 6 के जरिए आवेदन करते हैं, तो उसे झूठी घोषणा नहीं माना जाएगा, लिहाजा दंडनीय कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। आश्चर्यजनक है कि एक संवैधानिक संस्था ही संवैधानिक कानून के खिलाफ काम कर रही है! एसआईआर का अभियान 13 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में सम्पन्न हो चुका है। अंतिम मतदाता सूचियां भी जारी की जा चुकी हैं। कुछ संशोधन तो जारी रहेंगे, उनकी पूरक सूचियां प्रकाशित की जाएंगी। अभी तक के शुद्धिकरण में 3 करोड़ से अधिक ऐसे मतदाता सामने आए हैं, जिनका कोई अता-पता नहीं है। वे कौन हैं? किस मंगल ग्रह पर चले गए? कोई जानकारी नहीं है। वैसे यह बेहद अजीब स्थिति है, क्योंकि उनके नाम मतदाता सूची में रहे हैं। जाहिर है कि उन्होंने मतदान भी किया होगा! वे दिवंगत की सूची में भी नहीं हैं। उप्र के सीईओ नवदीप रिणवा ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि उप्र में 7-8 लाख लोग ऐसे रहे, जिन्होंने अधिकृत फॉर्म भर कर नहीं लौटाए। बीएलओ बार-बार उनके आवास पर गए। अब तो उन्होंने मिलना ही बंद कर दिया है। क्या उन्हें घुसपैठिए अथवा फर्जी मतदाता मान लिया जाए? ऐसे 3 करोड़ से अधिक पूर्व मतदाताओं को गृहमंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठिए करार दिया है। मगर सवाल है कि यह आंकड़ा अचानक कहां से आ गया?

धनतेरस: आरोग्य, धन और समृद्धि का पावन पर्व

योगेश कुमार गोयल

> **धनतेरस का वास्तविक संदेश केवल अधिक खरीदारी करना नहीं बल्कि धन के सदुपयोग, स्वच्छता, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का महत्व समझना है। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी निरोगी शरीर, परिवार की खुशियां, मानसिक शांति और परिश्रम से अर्जित समृद्धि है। भगवान धन्वंतरि की आराधना और यमदीपदान के माध्यम से यह पर्व जीवन की रक्षा, दीर्घायु और मंगलमय भविष्य की कामना का अनुपम अवसर बन जाता है।**

प्रतिवर्ष दीपावली से दो दिन पूर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व श्रद्धा, उल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 6 नवंबर को मनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में धनतेरस का विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसे केवल धन और वैभव की प्राप्ति का पर्व मानना उचित नहीं होगा बल्कि यह आरोग्य, दीर्घायु, सुख-समृद्धि और स्वस्थ जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर है। इस दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा-अर्चना की जाती है।

धनतेरस का इतिहास अत्यंत प्राचीन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। उन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार तथा आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। मान्यता है कि उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था, जो जीवन, स्वास्थ्य और अमरत्व का प्रतीक है। इसी कारण उन्हें देवताओं का वैद्य और आरोग्य का देवता कहा जाता है। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत के माध्यम से देवताओं को अमरत्व प्राप्त हुआ था। भगवान धन्वंतरि के इसी दिव्य प्राकट्य की स्मृति में धनतेरस मनाने की परंपरा प्रचलित हुई।

भगवान धन्वंतरि का संबंध केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि उनका आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा परंपरा में भी विशेष स्थान है। आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान माना गया है, जिसका उद्देश्य केवल रोगों का उपचार करना नहीं बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए दीर्घ एवं संतुलित जीवन प्रदान करना है। यही कारण है कि धनतेरस का दिन चिकित्सकों, वैद्यों और चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा कर लोग परिवार के आरोग्य, निरोगी काया और दीर्घायु की कामना करते हैं। धनतेरस हमें यह संदेश भी देता है कि वास्तविक धन केवल सोना, चांदी और संपत्ति नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति और संतोषपूर्ण जीवन है। इसलिए इस पर्व का मूल भाव धन के साथ आरोग्य और समृद्धि की मंगलकामना करना है।

धनतेरस के पर्व पर भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ मृत्यु के देवता यमराज के पूजन तथा दीपदान का भी विशेष विधान है। इस दिन संध्याकाल में घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर यमराज के निमित्त एक दीपक जलाया जाता है, जिसे ह्यायम दीपकह्न अथवा ह्यायमदीपदानह्न कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि तथा मंगल बना रहता है। इस परंपरा के पीछे अत्यंत रोचक और भावुक पौराणिक कथा प्रचलित है।

कथा के अनुसार, एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि प्राणियों के प्राण हरते समय क्या कभी ऐसा अवसर भी आया, जब किसी व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में दया उत्पन्न हुई हो और तुम्हारा हृदय करुणा से भर उठा हो? यमराज का प्रश्न सुनकर यमदूतों ने उत्तर दिया कि वे तो केवल उनकी आज्ञा का पालन करने वाले सेवक हैं। उनका कार्य निर्धारित समय पर जीवों के प्राण लेना है इसलिए दया और मोह-माया का उनके कार्य में कोई स्थान नहीं है। हालांकि, यमराज द्वारा निर्भय होकर सच बताने का आश्वासन दिए जाने पर उन्होंने एक ऐसी घटना का उल्लेख किया, जिसने उन्हें भी भीतर तक विचलित कर दिया था।

यमदूतों ने बताया कि एक बार हंस नाम का राजा शिकार के लिए जंगल में गया था। शिकार करते समय वह अपने साथियों से बिछुड़ कर दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। उस राज्य के राजा हेमा ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उसका खूब आदर-सत्कार किया। संयोगवश उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजपरिवार में खुशियां छा गई लेकिन ज्योतिषियों ने नवजात राजकुमार की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि विवाह के ठीक चार दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा और रानी शोकाकुल हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को इस अनिष्ट से बचाने के लिए उसे यमुना नदी के किनारे एक निर्जन गुफा में रखवा दिया। वहां उसके पालन-पोषण की राजसी व्यवस्था की गई और विशेष सावधानी बरती गई कि उस पर किसी युवती की छाया तक न पड़े। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।

एक दिन संयोगवश राजा हंस की पुत्री घूमते-घूमते यमुना तट पर पहुंच गई। वहां उसकी दृष्टि राजकुमार पर पड़ी और दोनों एक-दूसरे को देखते ही मोहित हो गए। उनके बीच प्रेम उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसी समय गंधर्व विवाह कर लिया। दुर्भाग्यवश, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के चार दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। यमदूतों ने यमराज को बताया कि उन्होंने अपने जीवन में उस नवविवाहित जोड़े जैसा सुंदर और प्रेमपूर्ण युगल कभी नहीं देखा था। दोनों कामदेव और रति के समान प्रतीत होते थे। राजकुमार के प्राण हरने के बाद जब उसकी नवविवाहिता पत्नी ने विलाप करना शुरू किया तो उसका करुण क्रंदन सुनकर यमदूतों का हृदय भी द्रवित हो उठा।

यह पूरा वृत्तांत सुनने के बाद यमराज ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरि के पूजन के साथ उनके निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु के भय से रक्षा होती है। तभी से धनतेरस पर यमदीपदान की परंपरा प्रचलित होने की मान्यता है। इसी विश्वास के चलते लोग संध्याकाल में घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर यमराज से परिवार के सभी सदस्यों की लंबी आयु और आरोग्य की प्रार्थना करते हैं। धनतेरस पर खरीदारी की भी विशेष परंपरा है। इस दिन पुराने और टूटे-फूटे बर्तनों के स्थान पर नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। अनेक लोग सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी खरीदते हैं। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आती हैं। कुछ परिवारों में नई झाड़ू खरीदकर उसका पूजन करने की भी परंपरा है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हुए इसे घर से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर करने का माध्यम माना जाता है।

दीपावली : दीप जलें, मन का अंधकार मिटे

डा. अनुज आचार्य

यदि घर में धन है, लेकिन रिश्तों में प्रेम नहीं, समाज में वैभव है, लेकिन गरीब के प्रति संवेदना नहीं, शिक्षा है, लेकिन चरित्र नहीं, तो ऐसी समृद्धि का वास्तविक मूल्य क्या है? लक्ष्मी की आराधना तभी सार्थक है जब धन के साथ सद्बुद्धि, ईमानदारी और परोपकार भी हमारे जीवन का हिस्सा बनें। दीपावली का धार्मिक महत्त्व किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं है। दक्षिण भारत में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर के वध को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस का विशेष महत्त्व है। सिख समुदाय इस अवसर को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है, जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी की मुक्ति और 52 राजाओं की रिहाई की स्मृति से जुड़ा है।



किसी जरूरतमंद के घर में दीप जलाना, किसी निराश व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना और किसी अकेले बुजुर्ग के साथ कुछ पल बिताना भी उतना ही पुण्यकारी है जितना मंदिर में दीप प्रज्वलित करना। वास्तव में दीपावली की सार्थकता इस बात से तय नहीं होगी कि हमने कितने दीप जलाए, बल्कि इससे होगी कि हमने अपने भीतर के अहंकार के कितने अंधेरों को मिटाया

दीपावली केवल दीप जलाने, मिठाइयां बांटने और घरों को सजाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति के उस शाश्वत दर्शन का प्रतीक है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान और अधर्म से धर्म की ओर बढ? की प्रेरणा देता है। कार्तिक मास की अमावस्या की काली रात में असंख्य दीपों का प्रज्वलित होना इस विश्वास को मजबूत करता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की एक छोटी-सी किरण उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। यही दीपावली का आध्यात्मिक सार और जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेतायुग में भगवान श्रीराम चौदह वर्ष का वनवास पूरा करने और लंकापति रावण का वध कर माता सीता तथा लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। मयार्दा पुरुषोत्तम श्रीराम के स्वागत में अयोध्यावासियों ने दीप प्रज्वलित कर पूरी नगरी को प्रकाशमय कर दिया था। यह प्रसंग केवल एक राजा की घर वापसी का उत्सव नहीं, बल्कि अहंकार पर विनम्रता, अन्याय पर न्याय और अधर्म पर धर्म की विजय का उद्घोष है। श्रीराम का जीवन हमें सिखाता है कि सत्ता से बड़ा कर्तव्य, अधिकार से बड़ा दायित्व और व्यक्तिगत स्वार्थ से बड़ा लोककल्याण होता है। दीपावली की अमावस्या को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष विधान है। लक्ष्मी समृद्धि की प्रतीक हैं और गणेश बुद्धि, विवेक तथा शुभारंभ के आराध्य। किंतु आज हमें स्वयं से यह प्रश्न भी पूछना चाहिए कि क्या केवल धन-संपत्ति अर्जित कर लेना ही समृद्धि है?

यदि घर में धन है, लेकिन रिश्तों में प्रेम नहीं, समाज में वैभव है, लेकिन गरीब के प्रति संवेदना नहीं, शिक्षा है, लेकिन चरित्र नहीं, तो ऐसी समृद्धि का वास्तविक मूल्य क्या है? लक्ष्मी की आराधना तभी सार्थक है जब धन के साथ सद्बुद्धि, ईमानदारी और परोपकार भी हमारे जीवन का हिस्सा बनें। दीपावली का धार्मिक महत्त्व किसी एक परंपरा तक सीमित नहीं है। दक्षिण भारत में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर के वध को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस का विशेष महत्त्व है। सिख समुदाय इस अवसर को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है, जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी की मुक्ति और 52 राजाओं की रिहाई की स्मृति से जुड़ा है। पूर्वी भारत में मां काली की आराधना होती है। इन विविध मान्यताओं में एक साझा संदेश छिपा है- मानवता, मुक्ति, न्याय और सद्भाव। यही भारतीय संस्कृति की वास्तविक शक्ति है कि अलग-अलग आस्थाएं होते हुए भी हमारे उत्सव एक-दूसरे के आनंद में सहभागी बनते हैं। धनतेरस से भाई दूज तक पांच दिनों तक चलने वाला यह उत्सव स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और पारिवारिक संबंधों की मधुरता का संदेश देता है। नरक चतुर्दशी बुराई के अंत, गोवर्धन पूजा प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण तथा भाई दूज भाई-बहन के आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। इस प्रकार दीपावली का प्रत्येक दिन जीवन के किसी न किसी महत्त्वपूर्ण मूल्य से जुड़ा हुआ है। इस पर्व का विद्यार्थियों के लिए विशेष संदेश है। जिस प्रकार एक दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना अथवा रोजगार हासिल करना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार, संवेदनशील और चरित्रवान नागरिक बनना है। आज विद्यार्थियों को यह समझने की आवश्यकता है कि अज्ञान का अंधकार पुस्तकीय ज्ञान से ही नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण आचरण से दूर होता है। झूठ, नकल, ईर्ष्या, नशा, अनुशासनहीनता और सामाजिक भेदभाव ऐसे अंधकार हैं जिन्हें जीवन से दूर करना ही सच्ची दीपावली है। विद्यार्थी संकल्प लें कि वे अपने ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए भी करेंगे।

विडंबना यह है कि जिस दीपावली का मूल संदेश प्रकाश और पवित्रता है, उसी अवसर पर हम प्रदूषण, दिखावे और अनावश्यक खर्च की होड़ में शामिल हो जाते हैं। लाखों रुपए आतिशबाजी पर खर्च कर दिए जाते हैं, जबकि आसपास ऐसे परिवार भी होते हैं जिनके घरों में आर्थिक अभाव के कारण दीप तक नहीं जल पाते। तेज आवाज वाले पटाखे बुजुर्गों, बच्चों, बीमार व्यक्तियों और पशु-पक्षियों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। क्या हमारी धार्मिक आस्था का तकाजा नहीं कि उत्सव मनाते समय दूसरों के अधिकार और सुविधाओं का भी ध्यान रखें? मिट्टी के दीये खरीदकर स्थानीय कुम्हारों को आर्थिक संबल देना, जरूरतमंदों के साथ खुशियां बांटना और पर्यावरण के अनुकूल दीपावली मनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज समाज को सबसे अधिक आवश्यकता आपसी विश्वास, सहिष्णुता और सामाजिक एकता की है। धर्म, जाति, भाषा और आर्थिक स्थिति के आधार पर बढ़ती दूरियां हमारी सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप नहीं हैं। दीपावली हमें सिखाती है कि प्रकाश किसी एक घर या वर्ग की संपत्ति नहीं होता, वह सबके लिए होता है।

इसलिए किसी जरूरतमंद के घर में दीप जलाना, किसी निराश व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना और किसी अकेले बुजुर्ग के साथ कुछ पल बिताना भी उतना ही पुण्यकारी है जितना मंदिर में दीप प्रज्वलित करना। वास्तव में दीपावली की सार्थकता इस बात से तय नहीं होगी कि हमने कितने दीप जलाए, कितनी मिठाइयां बांटीं या कितनी खरीददारी की, बल्कि इससे होगी कि हमने अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या, घृणा और स्वार्थ के कितने अंधेरों को मिटाया। आइए, इस दीपोत्सव पर संकल्प लें कि हमारे घरों के साथ हमारे विचार भी प्रकाशित होंगे, हमारी पूजा के साथ हमारा व्यवहार भी पवित्र होगा और हमारी खुशियों में समाज के अंतिम व्यक्ति की सहभागिता भी सुनिश्चित होगी। क्योंकि दीपावली का असली उत्सव तब है, जब दीप केवल घरों में नहीं, बल्कि इनसान के दिलों में भी जलें।

स्वच्छता के साथ जरूरतमंदों को राहत देने की पहल

ग्वालियर नगर निगम का अनूठा अभियान, 1 रुपये में मिल रहे घर के जरूरतमंद सामान

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



किसी के घर में जगह घेर रहा पुराना टीवी किसी के लिए मनोरंजन का नया साधन बन गया तो किसी के घर से निकला फ्रिज दूसरे परिवार के लिए बड़ी सुविधा। एक रुपये में टीवी, फ्रिज, आरओ और डबल बेड जैसे सामान पाकर जरूरतमंद परिवारों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। घर की जरूरत पूरी होने की खुशी थी... बाल भवन में गुरुवार को नगर निगम के स्वच्छ दीवाली एक रुपये वाली अभियान के तहत सामग्री वितरण के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सामान लेने पहुंचे लोगों के लिए यह महज एक रुपये में वस्तु खरीदने का अवसर नहीं था, बल्कि घर की जरूरत पूरी होने की खुशी थी। जरूरतमंद परिवारों के लिए ये सुविधाएं मिलना किसी बड़ी सौगात से कम नहीं कार्यक्रम में रूपसिंह स्टेडियम के पास निवास करने वाली ओमवती वाल्मीक अपने परिवार के लिए टीवी लेने पहुंचीं, तो वहीं मेंहदी वाले सैयद गोल पहाड़िया निवासी सुमन कुशवाह ने अपनी प्राथमिकता में फ्रिज को चुना। इरफान खान ने पलंग तो वहीं भावना ने आने वाले सर्दी के मौसम को देखते हुए रूम हीटर एक रुपये में खरीद लिया। जरूरतमंद परिवारों के लिए ये सुविधाएं मिलना किसी बड़ी सौगात से कम नहीं था। सिकंदर कंपू निवासी ममता ने शुद्ध पानी पीने के लिए आरओ खरीदा। सामान मिलने के बाद कई लोग इसे संभालकर घर ले जाने की व्यवस्था करते नजर आए। सामान वितरण कार्यक्रम के दौरान निगमायुक्त अभिषेक चौधरी, अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव, उपायुक्त एसबीएम मुकेश बंसल मौजूद थे।25 हजार से अधिक वस्तुएं आई अभियान में नगर निगम ने दीपावली के दौरान घरों से निकलने वाली उपयोगी वस्तुओं को कचरे में जाने से बचाने के लिए 21 अक्टूबर से यह अभियान शुरू किया था। इस वर्ष शहरवासियों ने 25067 वस्तुएं जमा कराई, जबकि पिछले साल यह संख्या करीब पांच हजार थी। इनमें 21318 कपड़े, 803 जोड़ी जूते, 844 बोतलें, 453 किताबें, 192 इलेक्ट्रानिक आइटम, 192 खिलौने, 451 कंबल और अन्य उपयोगी सामग्री शामिल है। अभियान के जरिए नगर निगम ने एक ओर जरूरतमंद परिवारों को उपयोगी सामान उपलब्ध कराया, वहीं दूसरी ओर पुनः उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। किसी के लिए अनुपयोगी हो चुकी वस्तु किसी दूसरे परिवार की जरूरत पूरी कर सकती है, इस सोच को शहरवासियों के सहयोग ने मजबूती दी है।

'चौराहों पर तैनात पुलिस को ओवरलोड वाहन क्यों नहीं दिखते?' ग्वालियर हाई कोर्ट की फटकार

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए क्षमता से अधिक संख्या में बच्चों को बैठाकर ले जाने वाले ऑटो-रिक्शा और वाहनों के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बुधवार को पुलिस और परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। 'क्या चौराहों पर पुलिस को ओवरलोड वाहन नजर नहीं आते?' न्यायमूर्ति अमित सेठ की एकल पीठ ने अधिकारियों से तीखे सवाल करते हुए कहा कि जब हम और आप सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो क्या सड़कों पर यह दिखाई नहीं देता कि बच्चों को वाहनों में भूसे की तरह भरकर ले जाया जाता है। पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि हर प्रमुख चौराहे पर पुलिस तैनात रहती है, इसके बावजूद इन ओवरलोड स्कूली वाहनों पर पुलिस और परिवहन विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ती? अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त रुख कोर्ट की इस फटकार के बाद अब ग्वालियर में ओवरलोड स्कूली वाहनों, ऑटो और वैनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सख्ती और जांच अभियान चलाए जाने की संभावना है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मासूम बच्चों की जान जोखिम में डालने वाले ऐसे लापरवाही पूर्ण रवैये को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदार विभागों को इस पर तुरंत ठोस कदम उठाने होंगे।

ग्वालियर में पाम ऑयल से बन रहा था नकली मावा, छापेमारी में बिना लाइसेंस चल रहे 12 कारखाने सील

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



त्योहारी सीजन में नकली दूध-मावा का कारोबार भिंड-मुरैना में ही नहीं ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों में भी जमकर हो रहा है। बुधवार को घाटीगांव के भंवरपुरा इलाके में 12 ठिकानों पर एसडीएम घाटीगांव जूही गर्ग व टीम ने छापेमारी की, जहां पाम ऑइल से मावा तैयार किया जा रहा था। कई कारखानों के पास लाइसेंस तक नहीं था। मावा व दूध का बड़ा स्टाक मिला। खास बात यह कि भंवरपुरा थाने की सीमा में ही सबसे ज्यादा मावा तैयार करने के ठिकाने थे। मौके पर जो लोग मिले वे यह भी नहीं बता पाए कि कौन कारोबार करता है। इनका पूरा माल ग्वालियर सप्लाई होता है।

फर्जी पासपोर्ट मामला : चुनौती बने बौद्ध भिक्षु बांग्लादेशी, कुछ विदेश भागे ; अब फंडिंग की पड़ताल पर फोकस

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



फर्जी दस्तावेजों के जरिए बौद्ध भिक्षु बनकर पासपोर्ट बनवाने वाले आरोपियों का यह मामला मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। एसटीएफ अब तक इस गिरोह के सरगना रियाल चौधरी, दोनों गवाहों और पासपोर्ट सेवा केंद्र के एक कर्मचारी सहित कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इसके आगे की कड़ियां जोड़ने में जांच एजेंसी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जांच में यह बात सामने आई है कि फर्जी तरीके से बौद्ध भिक्षु बने बांग्लादेशी नागरिकों में से कई आरोपी विदेश भाग चुके हैं, जबकि कुछ देश के अलग-अलग राज्यों में छिपकर रह रहे हैं। आरोपियों के इस तरह देश-विदेश में फैल जाने के कारण एसटीएफ को उन्हें पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एसटीएफ का मुख्य फोकस इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग की जांच पर है। पड़ताल में खुलासा हुआ है कि गिरोह का सरगना रियाल चौधरी ग्वालियर के रहने वाले गुलाबराय गौतम उर्फ भंते सम्यक बोधि के बैंक खाते का इस्तेमाल कर रहा था। एसटीएफ अब इन संदिग्ध बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की गहराई से छानबीन कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस फर्जीवाड़े के पीछे किन लोगों और संस्थाओं से फंडिंग हो रही थी।

मौसम के उतार-चढ़ाव ने लोगों को किया हैरान

नवंबर की शुरुआत में ग्वालियर में गर्मी का असर बरकरार, अधिकतम तापमान 33 डिग्री पहुंचा

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



नवंबर की शुरुआत में भी ग्वालियर का मौसम गर्म बना हुआ है। बुधवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान वाले शहरों में ग्वालियर शामिल रहा। शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। प्रदेश में मंडला 33.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि ग्वालियर का तापमान भी इससे महज आधा डिसे कम रहा। इससे साफ है कि नवंबर में भी शहरवासियों को दोपहर की गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम का मिजाज दिन और रात में बना हुआ है अलग-अलग मौसम का मिजाज दिन और रात में अलग-अलग बना हुआ है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिसे अधिक रहा। मंगलवार की तुलना में रात के तापमान में 1.2 डिसे की गिरावट आई, लेकिन दिन का तापमान 32.5 से बढ़कर 33 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह हल्की ठंड महसूस हुई, लेकिन दोपहर में तेज धूप ने गर्मी का अहसास कराया। नवंबर शुरू हो चुका है लेकिन दिन में अभी भी गर्मी का असर है। सुबह 19 डिसे, दोपहर में 33 डिसे तक चढ़ा पारा बुधवार को सुबह साढ़े पांच बजे तापमान 17.2 डिग्री और साढ़े आठ बजे 19 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह हवा में नमी 86 प्रतिशत रही। इसके बाद धूप तेज होने के साथ तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। सुबह साढ़े 11 बजे पारा 29.2 डिग्री सेल्सियस और दोपहर ढाई बजे 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिन और रात के तापमान में करीब 17 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। इस तरह ग्वालियर में रात को हल्की ठंड और दिन में गर्मी का दौर बना हुआ है।

त्योहार पर गुजरात जाने वालों को राहत, ग्वालियर होकर असारवा के लिए चलेगी एकतरफा विशेष फेस्टिवल ट्रेन

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चार एकतरफा विशेष ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। इसमें ग्वालियर के यात्रियों के लिए भी एक विशेष ट्रेन की सुविधा शामिल की गई है। गाड़ी संख्या 01826 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-असारवा विशेष ट्रेन 5 नवंबर को ग्वालियर स्टेशन पर ठहराव लेकर आगे के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन के शुरू होने से गुजरात की तरफ जाने वाले यात्रियों को एक अतिरिक्त और सुलभ विकल्प मिलेगा। सुबह 9:10 बजे आगे के लिए होगी रवाना समय-सारणी के अनुसार, यह विशेष ट्रेन 5 नवंबर को सुबह 7:30 बजे झांसी स्टेशन से प्रस्थान करेगी और सुबह 9:05 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। ग्वालियर स्टेशन पर 5 मिनट का ठहराव लेने के बाद सुबह 9:10 बजे ट्रेन आगे के गंतव्य के लिए रवाना होगी। प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए असारवा पहुंचेगी ग्वालियर से रवाना होकर यह ट्रेन आगरा कैंट, भरतपुर, बांदीकुई, जयपुर, अजमेर, मारवाड़ जंक्शन और आबू रोड जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव लेगी। इसके बाद अगले दिन, यानी 6 नवंबर को सुबह 7:30 बजे असारवा (गुजरात) स्टेशन पहुंचेगी। रेलवे के इस कदम से त्योहारी सीजन में राजस्थान और गुजरात की ओर जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी।

रेलवे स्टेशन पर रील बनाने वालों की अब खैर नहीं झांसी मंडल ने सुरक्षा नियमों पर दी कड़ी चेतावनी

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और व्यूज हासिल करने की होड़ में रेलवे सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर अब गाज गिरना तय है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन, चलती ट्रेनों और रेल पटरियों पर बिना अनुमति वीडियो या ब्लॉग बनाने वालों को झांसी रेल मंडल ने कड़ी चेतावनी दी है। सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर रील बनाने वालों के खिलाफ अब रेलवे सख्त कानूनी कदम उठाने की तैयारी में है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में वीडियो बनाने पर कानूनी कार्रवाई झांसी रेल मंडल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि रेलवे स्टेशन परिसरों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश, पटरियों पर खतरनाक स्टंट और बिना अनुमति शूटिंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे प्रशासन ऐसे मामलों में शामिल व्यक्तियों पर संबंधित कानूनी धाराओं के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई करेगा, ताकि यात्रियों और रेल परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भ्रामक और आधी-अधूरी जानकारी फैलाने पर नजर रेलवे प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कई यूट्यूब चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए रेल परिचालन से जुड़ी भ्रामक और आधी-अधूरी सामग्री प्रसारित की जा रही है। इन वीडियो में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है, जिससे यात्रियों के बीच गलतफहमी फैलती है। रेलवे ने ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निगरानी रखने का निर्णय लिया है।

बहू की बीमारी ने बनाया चोर...

कर्ज में डूबी महिला ने आगरा से उड़ाए 25 लाख के गहने

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



सुल्तानपुरा बाजार में सर्राफ की दुकान से 15 लाख के जेवरात चोरी करने की वारदात ग्वालियर की महिला शकीला ने की थी। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन से पांच किलोमीटर की दूर स्थित उसके घर के निकट तक 200 सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग को खंगाला। आरोपी महिला के मोहल्ले तक पहुंचने के बाद उसका फोटो दिखाकर पहचान के बाद पकड़ लिया गया। महिला से 25 लाख के जेवरात बरामद किए हैं। जो अन्य दुकानों से चोरी किए बताए गए हैं। अरोपी महिला शकीला पुलिस को बताया, कुछ वर्ष पहले बहू की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उसके उपचार में जमा पूंजी खर्च हो गई और नाती-नातिन की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। कुछ महीने पहले एक दुकान से जेवरात चोरी करने पर नहीं पकड़ी जाने पर उसने दोबारा वारदात की। आगरा सदर के सुल्तानपुरा बाजार में 31 अक्टूबर को सर्राफ सौरभ अग्रवाल की दुकान पर ग्राहक बनकर आई महिला 15 लाख रुपये की सोने की चूड़ियां चोरी कर ले गई थी। आरोपी महिला ने दुकान से बाहर निकलने के बाद नकाब पहन लिया। इसके बाद वह कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची और ग्वालियर की ट्रेन में सवार हो गई। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से कैंट रेलवे स्टेशन तक पहुंची। आरोपी शकीला ट्रेन से रास्ते में नहीं उतरी। ग्वालियर पर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वह भीड़ में गुम हो गई थी। पुलिस टीम ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला अपर पुलिस उपायुक्त नगर मनोज ने बताया कि पुलिस टीम ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। उनकी मदद से करीब पांच किलोमीटर तक पीछा कर पुलिस आरोपित शकीला के मोहल्ले तक पहुंची। वहां उसका फोटो दिखाने पर लोगों ने उसका नाम बताया। आरोपी शकीला के घर से सर्राफ के यहां से चोरी की गई सोने की चूड़ियों समेत 25 लाख के जेवरात बरामद किए गए हैं। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि महिला से बरामद बाकी जेवरात उसने अन्य दुकानों से चोरी किए थे।

प्रदेश का रोड नेटवर्क मास्टर प्लान 2027-2047 तैयार

सड़क नेटवर्क की गुणवत्ता जांचने की तैयारी, 55 हजार किमी का होगा आकलन

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर



प्रदेश में आगामी दो दशकों के सड़क विकास की दिशा, व्यापक प्राथमिकताओं और भविष्य की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को तय करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक महत्वाकांक्षी तथा वृहद 'रोड नेटवर्क मास्टर प्लान' तैयार करने जा रही है। वर्ष 2027 से 2047 तक की 20 वर्षीय अवधि के लिए बनाए जाने वाले इस दूरगामी मास्टर प्लान के अंतर्गत राज्य के लगभग 55 हजार किलोमीटर लंबे विशाल सड़क नेटवर्क का गहन सर्वे, डिजिटल मैपिंग और आधुनिक यातायात विश्लेषण किया जाएगा। इस व्यापक अध्ययन और विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर ही आने वाले वर्षों में यह तय किया जाएगा कि किन-किन मुख्य राजमार्गों का चौड़ीकरण करना अनिवार्य है, यातायात के दबाव वाले शहरों में नए बाइपास और आउटर रिंग रोड बनाने की आवश्यकता कहां-कहां है, किन-किन नदी-नालों तथा रेल क्रॉसिंग पर नए ओवरब्रिज या फ्लाइओवर की सख्त जरूरत है और प्रदेश के सुदूर या पिछड़े क्षेत्रों को राज्य की मुख्य आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए बेहतर सड़क कनेक्टिविटी का खाका किस तरह तैयार किया जाए। औद्योगिक विकास, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स पर विशेष ध्यान इस दूरगामी और व्यापक योजना में केवल नई सड़कों के निर्माण या मरम्मत तक सीमित न रहकर राज्य के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखा गया है। मास्टर प्लान में प्रदेश के तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्रों, माल ढुलाई के प्रमुख गलियारों, कृषि उपज मंडियों, प्रसिद्ध पर्यटन व धार्मिक स्थलों की सुगम पहुंच और भविष्य की बढ़ती आबादी तथा वाहनों के दबाव का विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा। इससे कृषि उपज को बाजारों तक जल्दी पहुंचाने और औद्योगिक उत्पादों के सुगम परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई व मजबूत गति मिलने की पूरी उम्मीद है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ कंसल्टेंसी सेवाओं के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पूरे सर्वेक्षण और वृहद रिपोर्ट को 18 महीने की निर्धारित समय-सीमा के भीतर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में एमपीआरडीसी और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के 'रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम' (रैम्स) के पास लगभग 30 हजार किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे और मुख्य जिला मार्गों का विस्तृत डिजिटल डेटा पहले से ही उपलब्ध है, जिसका उपयोग इस नए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने और भविष्य की सड़क नेटवर्क रणनीति तैयार करने में प्रभावी ढंग से किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

अपने ही कस्टमर से मुकाबला करना अच्छी रणनीति नहीं, अडानी ग्रुप का एयरलाइंस सेक्टर में उतरने से इनकार

नई दिल्ली, एजेंसी। मुंबई, लखनऊ और अहमदाबाद समेत देश के 9 एयरपोर्ट चला रहा अडानी ग्रुप फिलहाल एयरलाइंस सेक्टर में प्रवेश नहीं करेगा। ग्रुप का ध्यान अपने एयरपोर्ट कारोबार के विस्तार पर है। आने वाले समय में देश के 11 और एयरपोर्ट के निजीकरण की प्रक्रिया में भी वह हिस्सा लेगा। यह जानकारी मंगलवार को एयरोसिटी में चल रहे एविएशन इंडिया एंड साउथ एशिया 2026 कॉन्फ्रेंस में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के ष्टश्वह्व अरुण बंसल ने दी। एयरलाइन कारोबार में



उतरने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए बंसल ने कहा कि एयरलाइंस की ग्राहक हैं और अपने ग्राहकों से प्रतिस्पर्धा करना अच्छी रणनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि ।रुऔर अडानी ग्रुप को अलग-अलग देखा जाना चाहिए। हाल में आई थी कि अडानी ग्रुप एयरलाइन बिजनेस में उतर सकता है और इसके लिए उसने सरकार से नियमों में बदलाव करने का अनुरोध किया है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इसका खंडन किया था। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया था कि एयरलाइन बिजनेस में उतरने पर विचार करने वाली खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेटर किसी शेड्यूल्ड एयरलाइन में 10% से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकते हैं। अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। माना जा रहा था कि सरकार एयर इंडिया और इंडिगो के दबदबे को खत्म करने के लिए यह नियम बदलने पर विचार कर रही है। अभी इन दोनों कंपनियों की डोमेस्टिक मार्केट में करीब 90 फीसदी हिस्सेदारी है। हालांकि एयरलाइन कंपनियों ने इसका विरोध किया है। उनका तर्क है कि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को एयरलाइन का मालिक बनने की अनुमति देने से हितों का भारी टकराव पैदा होगा। साथ ही इससे कंज्यूमर्स को नुकसान हो सकता है। सरकार वाराणसी, अमृतसर और रायपुर समेत 11 एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है।

अनिल अंबानी ग्रुप पर कसता शिकंजा, अब तक 23,100 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली, एजेंसी। रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने सख्त कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने 2 चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, जमीन के टुकड़ों और पवन चक्कियों समेत 510 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। एजेंसी का आरोप है कि ग्रुप ने रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के जरिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सार्वजनिक धन की हेराफेरी की। उसे व्यक्तिगत लाभ और टैक्स हैवन देशों में डायवर्ट किया है। मंगलवार को अनिल अंबानी समूह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 510 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में की गई है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। 247.12 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई। इनमें डसॉल्ट फाल्कन 2000 और एम्ब्रेयर के दो चार्टर्ड विमान, महाराष्ट्र में 6 जमीन के प्लॉट और एक ऑफिस परिसर शामिल हैं। वहीं, मामले में 263.05 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई। इसमें तमिलनाडु की दो पवन चक्कियां, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और निवेश शामिल हैं।

साबुत चावल तो छोड़िए, टूटे चावल भी लगा रहा है छलांग, निर्यात पर लगेगा प्रतिबंध

नई दिल्ली, एजेंसी। महंगे होते चावल के दाम ने सरकार की नींद उड़ा दी है। शायद यही वजह है कि अब फूड कार्पोरेशन या के सरप्लस चावल से बनने वाले इथेनॉल की ऊपरी सीमा तय यानी कर दी गई है। इससे पहले चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब खबर आई है कि खुले बाजार में शत प्रतिशत टूटे हुए चावल या कीमतों में भी तेज उछ्रल हो रहा है। इसे देखते हुए हो सकता है कि सरकार इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे। वैसे भी इस साल अभी तक धान का उत्पादन घटने की ही खबर आई है।

पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट के लिए हर साल सरकार की तरफ से टेंडर निकाला जाता है। इसी टेंडर में इथेनॉल निर्माण और सप्लाई से जुड़ी नियम एवं शर्तों की जानकारी होती है। सरकार की तरफ से 3 नवंबर 2026 को जारी रिवाइज्ड टेंडर कंडीशंस में बताया गया है कि इस साल के शुरुआती तीन तिमाहियों में एफसीआई के सरप्लस चावल से 3.24 अरब लीटर से अधिक इथेनॉल नहीं बनाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत में गन्ने के रस के अलावा



चावल और मक्का का इथेनॉल बनाने में उपयोग होता है। चावल में भी अधिकतर टूटे चावल का ही उपयोग इसे बनाने में होता है। कीमतों में बढ़ोतरी पर ध्यान देना होगा चावल निर्यातकों के संगठन इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के महानिदेशक विनोद कौल का कहना है कि चावल की कीमतों में इस बढ़ोतरी पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। उनका कहना है कि इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रोकन राइस की कीमत बढ़ कर 360 डॉलर प्रति टन के ऊपर चला गया है। ऐसे में निर्यात करना पहले से ज्यादा फायदेमंद हो गया है। लेकिन सरकार भी चाहेगी कि इस तरह के चावल की घरेलू उपलब्धता बनी रहे। इसलिए हो सकता है कि इस इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे।

चावल की कीमत में बढ़ोतरी

बीते कुछ महीनों के दौरान ही चावल की कीमतों में खासी बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह विदेशी बाजारों में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी, देश में धान की बुवाई के रकबे में कमी और कुछ और कारण बताए जा रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी आंकड़ों को देखें तो 2 नवंबर 2026 को चावल की अखिल भारतीय औसत थोक कीमत 4380.49 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई थी। मतलब कि करीब 44 रुपये प्रति किलो। यह एक साल पहले इसी तारीख को 3747.44 रुपये प्रति क्विंटल था। यानी एक साल में ही चावल के दाम करीब 17 फीसदी बढ़ गए।

टूटे चावल का दाम भी बढ़े

उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक बीते एक पखवाड़े में टूटे चावलों की कीमतों में भी 5 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने 10 अक्टूबर को ब्रोकन राइस की ऑल इंडिया एवरेज प्राइस 2883 रुपये प्रति क्विंटल थी। यह दो नवंबर 2026 को बढ़ कर 3036 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में कम से कम टूटे चावलों का निर्यात तो रोक ही सकती है। चावल की कीमतों में इस बढ़ोतरी पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रोकन राइस की कीमत बढ़ कर 360 डॉलर प्रति टन के ऊपर चली गई है। केंद्र सरकार के कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल खरीफ मौसम के दौरान धान की फसल की बुवाई में 3.46 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। एक साल पहले इस दौरान 449.18 लाख एकड़ में धान की फसल बोई गई थी। इस साल यह क्षेत्र घट कर 433.62 लाख एकड़ रह गया है। खरीफ फसल में धान की बुवाई का रकबा घटने की मुख्य वजह मानसूनी बारिश की कमी से जोड़ा जा रहा है।

60 महीने पहले शुरुआत, अब हर साल 6 करोड़, नौकरी छोड़ने के बाद ऐसे खड़ा किया बिजनेस

यह ब्रांड बांस और कॉटन-लाइक्रा के ब्लेंड वाले टी-शर्ट और इनरवेयर बनाता है



नई दिल्ली, एजेंसी। यह कहानी है सुप्रीत कश्यप की। वह मैसूर के रहने वाले हैं। 2017 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वह एक्सेंचर में नौकरी करने लगे थे। फिर उन्होंने नौकरी छोड़कर अक्टूबर 2021 में अपने स्टार्टअप की नींव रखी। इसका नाम 'वेलबी' है। यह ब्रांड बांस और कॉटन-लाइक्रा के ब्लेंड वाले टी-शर्ट और इनरवेयर बनाता है। आज इसका सालाना टर्नओवर 6 करोड़ रुपये पहुंच गया है। आइए, यहां सुप्रीत कश्यप की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। ब्रांड को छोड़कर सुप्रीत के ब्रांड को चुनने से इसके क्र2क्रकारोबार में दोगुना उछाल आया। हर महीने ब्रांड 20,000 से अधिक उत्पाद बेचता है। यह स्टार्टअप साबित करता है कि सही प्रोडक्ट क्वालिटी और धैर्य के साथ स्थापित दिग्गजों को भी कड़ी टक्कर दी जा सकती है।

नौकरी छोड़कर की शुरुआत

सुप्रीत कश्यप मैसूर के एक मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं। उनके परिवार में पहले किसी ने बिजनेस नहीं किया था। सुप्रीत ने 2017 में इंजीनियरिंग पूरी की। फिर एक्सेंचर में 6 लाख रुपये के पैकेज पर नौकरी करने लगे। हालांकि, उनका मन नौकरी में नहीं लगा। एक साल में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर दिल्ली से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया। अक्टूबर 2021 की बात है। उन्होंने 10 लाख की सेविंग और माता-पिता की मदद से 'इको एम्ब्रेस डिजाइनर क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड' के तहत 'वेलबी' ब्रांड की शुरुआत की। शुरुआत में हाथ से बने प्रोडक्ट बेचने में असफलता मिली। इसके बाद उन्होंने बांस के रेशों से बने कपड़ों का रुख किया। 999 रुपये की एक राउंड-नेक टी-शर्ट से अपने ब्रांड की औपचारिक शुरुआत की।

सामने आईं कई चुनौतियां

यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। कंपनी का पहले साल का रेवेन्यू सिर्फ 11.5 लाख रुपये रहा। 2024 की पहली छमाही में कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपये का घाटा हो रहा था। स्टार्ट-अप के लिए मल्टी-टास्किंग कर्मचारी तलाशना और फैब्रिक की क्वालिटी तय करना बड़ी चुनौतियां थीं। हालांकि, उत्पादों की बेहतरीन क्वालिटी, पसीना सोखने की क्षमता और कम्फर्ट के चलते पुराने ग्राहकों के दोबारा खरीदारी करने से सुप्रीत का हौसला बढ़ा। 2023 में 75 लाख रुपये और 2024 में 2.5 करोड़ रुपये की बिक्री करके पिछले वित्तीय वर्ष में ब्रांड का टर्नओवर 6 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। इसमें करीब 60 कर्मचारियों की टीम काम कर रही है। ब्रांड के बांस के कपड़े तिरुपुर (तमिलनाडु) में बनते हैं। बेंगलुरु के नेलमंगला में इसका 5,500 वर्ग फीट का मुख्य वेयरहाउस है। इसका फोकस तेजी से बदलते फैशन के बजाय आराम पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्राहकों की तारीफ के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों और ग्राहकों ने खुद कंपनी में 3 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट फंड लगाया। अभी इसकी 97 फीसदी बिक्री अपनी वेबसाइट के अलावा अमेजन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होती है। बाकी 3 फीसदी मैसूर और मुंबई स्थित दो ऑफलाइन स्टोर्स से आती है। सीधे ग्राहकों को प्रोडक्ट बेचने के अलावा ब्रांड ने कॉर्पोरेट सेगमेंट में भी तेजी से कदम बढ़ाए हैं। जेरोधा, मेटा, जेडब्ल्यू मैरियट, सिस्को, अमेजन और एडोब जैसी टॉप कंपनियां अब अपने कर्मचारियों के लिए इसकी बैम्बू-ब्लेंड टी-शर्ट्स ऑर्डर करती हैं।

अमेरिका में चुनाव और जापान में हाहाकार! तीन महीने के लो पर पहुंचा शेयर बाजार



नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका के आज हो रहे मिडटर्म चुनावों पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं। निवेशकों को यह जानने की उत्सुकता है कि इसके बाद वैश्विक राजनीति में स्थिरता आएगी या नहीं। यह खासकर इक्विटीज के लिए बेहद अहम है। इन चुनावों से तय होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले दो साल के कार्यकाल के दौरान अमेरिका में कौन सी पार्टी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव और सीनेट को कंट्रोल करेगी। बाजार में तेजी आई है लेकिन जापान में स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। शुरुआती रुझानों में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत से एआई से जुड़े शेयरों में भारी गिरावट आई है और निक्केई तीन महीने के लो पर चला गया। माना जा रहा है कि डेमोक्रेट्स की जीत से डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को लेकर नियम सख्त हो सकते हैं। साथ ही एआई इन्फ्रा पर कंपनियों के खर्च में गिरावट आ सकती है। निक्केई शेयर एवरेज 3.56 फीसदी गिरावट के साथ 60,835.36 अंक पर आ गया जो 29 जुलाई के बाद इसका न्यूनतम स्तर है। ब्रॉडर टॉपिक्स भी 2.45 फीसदी गिरावट के साथ 3832.27 अंक रह गया। निवेशकों को आशंका है कि डेमोक्रेटिक का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। इससे एआई इन्फ्रा पर सख्ती हो सकती है जिसका व्यापक असर टेक, हेल्थकेयर, बैंकिंग और क्रिप्टोकरेंसीज जैसे सेक्टर पर पड़ सकता है।

इस दिवाली घर ही नहीं, अपने पोर्टफोलियो को भी चमकाएं

नई दिल्ली, एजेंसी। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड्स तक के निवेशक और ट्रेडर्स अपने पोर्टफोलियो का काफी ध्यान देते हैं। वे समय के साथ-साथ इसको देखते हैं और इसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव भी करते हैं। इसके लिए वे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को तगड़ी रणनीति के साथ करते हैं। वहीं, इस दौरान देश के लोगों में दिवाली का उमंग देख जा रहा है। लोग इस खास त्योहार को लेकर अपने घरों को चमकाने में लगे हुए हैं। इस बीच एक्सपर्ट का कहना है कि दिवाली पर केवल घरों को ही ना चमकाएं बल्कि अपने पोर्टफोलियो को भी चमकाएं। आइए जानते हैं कि इस दिवाली



आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे 'सुपर-रीसेट' कर सकते हैं। इसके लिए हम यहां एक्सपर्ट के जरिए आपको खास 5 स्टेप बताने जा रहे हैं।

कैसे करें अपने पोर्टफोलियो को रीसेट

लोग अपने पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई निवेश के रूप में रखते हैं। मतलब कि अपने 100 फीसदी फंड को किसी एक जगह निवेश ना करके कई जगहों पर निवेश किए होते हैं। इनमें इमरजेंसी फंड, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स एसआईपी समेत अन्य निवेश शामिल होते हैं। इसके अलावा लोग लोन, इंश्योरेंस और लायबिलिटीज को लेकर भी अपने पोर्टफोलियो में हिसाब रखते हैं।

अब आइए जानते हैं कि इन निवेश और खर्च को लेकर अपने पोर्टफोलियो को कैसे रीसेट किया जाता सकता है। इन्हें हम एक्सपर्ट से कुल 5 स्टेप के जरिए समझेंगे, जिसे हमारे सहयोगी ईटी वेल्थ की एक रिपोर्ट में बताया गया है।

फाउंडेशन करें चेक छह महीने की इमरजेंसी सेविंग्स बनाए रखें। टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस को रिव्यू करें। लोन और लायबिलिटीज़ का हिसाब रखें।

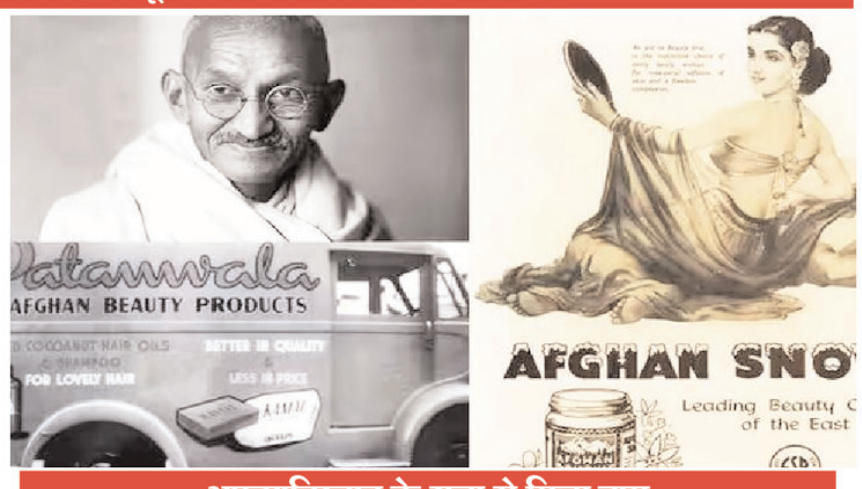
कब बढ़ेगी सैलरी और पेंशन 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनर्स का सवाल

नईदिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अहम अपडेट है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को एक साल, 3 नवंबर 2026 को ही पूरा हो गया। करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनर्स का सबसे बड़ा सवाल यह है कि सैलरी और पेंशन कब बढ़ेगी बता दें आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से मई 2027 के आसपास आयोग अपनी रिपोर्ट दे सकता है। वहीं, कर्मचारी संगठनों की ओर से 8वें वेतन आयोग के सामने मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने और 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग रखी गई है। हालांकि, यह कर्मचारियों की मांग है, न कि आयोग की ओर से तय की गई सैलरी। आयोग अपनी सिफारिशों में क्या प्रस्ताव देता है और सरकार उसे कितना मंजूर करती है, यह बाद में स्पष्ट होगा।

एक नाम जिसे बचाने के लिए महात्मा गांधी आए थे सामने

, भारत की पहली ब्यूटी क्रीम 'अफगान स्नो' की कहानी

नई दिल्ली, एजेंसी। अफगान स्नो। भारतीय कॉस्मेटिक इतिहास में इसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। साल 1919 में यह लॉन्च हुई थी। भारत की यह पहली मल्टीपर्पज ब्यूटी क्रीम थी। इसके साथ राजा-महाराजाओं का नाम, महात्मा गांधी का आशीर्वाद, बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों और भारत की पहली 'मिस इंडिया' प्रतियोगिता का इतिहास जुड़ा है। आधुनिक दौर की गोरेपन का दावा करने वाली क्रीमों के उलट अफगान स्नो ने कभी रंगभेद को बढ़ावा नहीं दिया। हालांकि, विदेशी नाम और पैकेजिंग के चलते स्वदेशी आंदोलन में घिरे इस ब्रांड को बचाने के लिए खुद महात्मा गांधी को सामने आना पड़ा था। लेकिन, बाद में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बड़े बजट और प्रतिस्पर्धा के आगे इसका प्रभाव समय के साथ कम होता चला गया।इसके बाद भारतीय जनता ने इसका बहिष्कार खत्म किया। साथ धीरे-धीरे प्रोडक्ट की चमक फीकी पड़ने लगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एंट्री और 'फेयर एंड लवली' जैसे गोरेपन का दावा करने वाले भारी-भरकम विज्ञापन बजट वाले उत्पादों के आने से प्रतिस्पर्धा बहुत मुश्किल हो गई।



अफगानिस्तान के राजा से मिला नाम

1909 की बात है। राजस्थान के राजपूताना से मुंबई (तब बॉम्बे) पहुंचे महत्वाकांक्षी उद्यमी इब्राहिम सुल्तानअली पाटनवाला ने इत्र और सौंदर्य प्रसाधनों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। 1919 में जब अफगानिस्तान के राजकुमार (जो बाद में राजा बने) भारत दौरे पर आए तो पाटनवाला ने उन्हें अपने उत्पादों का हैम्पर भेंट किया। उसी हैम्पर में बिना नाम वाले जार में रखी मोती जैसी सफेद ऑल-पर्पज क्रीम भी थी। क्रीम को देख राजकुमार ने कहा कि यह उन्हें अफगानिस्तान की बर्फ की याद दिलाती है। इस तरह भारत की पहली ब्यूटी क्रीम को 'अफगान स्नो' नाम मिला। यह क्रीम सिर्फ मॉइश्चराइजर नहीं थी। इसके बजाय मेक-अप बेस और सनस्क्रीन के रूप में भी इसका प्रचार होता था। इसे भारत के राजघरानों का भी खूब संरक्षण मिला।

पहली 'मिस इंडिया' प्रतियोगिता की स्पॉन्सरशिप

पाटनवाला ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया। इसके बजाय अपनी मजबूत व्यावसायिक दूरदर्शिता से इसे बॉम्बे के उच्च वर्ग में स्थापित भी किया। वह बड़े बॉल रूम डांस और पार्टियों का आयोजन करते थे। इनमें नरगिस, राज कपूर और देविका रानी जैसी मशहूर बॉलीवुड हस्तियां शामिल होती थीं। देविका रानी ने तो इसे 'ईश्वर का उपहार' बताकर इसका प्रमोशन किया था। यही नहीं, पाटनवाला की कंपनी ने 1952 में बॉम्बे में आयोजित भारत की पहली 'मिस इंडिया' प्रतियोगिता को भी स्पॉन्सर किया था। इसमें इंद्राणी रहमान विजेता बनी थीं। सबसे खास बात यह रही कि उस दौर में भी अफगान स्नो ने त्वचा के रंग को गोरा करने का कोई दावा नहीं किया। इसके बजाय यह प्रदूषण से त्वचा को बचाने और प्राकृतिक सुंदरता निखारने पर केंद्रित रही। हालांकि, 'अफगान स्नो' की इस कामयाबी के साथ अनोखा विवाद भी जुड़ गया। वैसे तो यह प्रोडक्ट पूरी तरह स्वदेशी था। लेकिन, इसकी खुशबू स्विट्जरलैंड के फॉर्मूलेशन से तैयार होती थी। कांच की बोतलें जर्मनी से आती थीं। लेबल जापान में छपते थे। इस विदेशी नाम और पैकिंग के चलते स्वदेशी आंदोलन के चरम पर भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे विदेशी सामान समझ इसका बहिष्कार शुरू कर दिया। संकट में फंसे पाटनवाला ने महात्मा गांधी से मदद मांगी। गांधी जी ने खुद एक बयान और विज्ञापन जारी कर देशवासियों को साफ किया कि 'अफगान स्नो' पूरी तरह से देसी उत्पाद है।

कैब ड्राइवर और डिलीवरी बॉय को मिलेंगे कई तरह के बेनिफिट्स

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में 1.2 करोड़ से अधिक गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। किसी कंपनी या डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए शॉर्ट टर्म, प्रोजेक्ट-बेस्ड या ऑन-डिमांड काम करने वाले लोगों को गिग वर्कर्स



कहते हैं। डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर और सर्विस प्रोवाइडर इस कैटगरी में आते हैं। सरकार ने गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का गठन किया है। उनके सोशल सिक्योरिटी को फंड करने के लिए सरकार एग्रीगेटर्स के कुल टर्नओवर के बजाय हर ट्रांजैक्शन पर 2 फीसदी लेवी लगाने पर विचार कर रही है। इस बोर्ड की इस महीने के सेकेंड हाफ में मीटिंग होगी जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी स्कीम की रूपरेखा पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस बारे में हो रही चर्चाओं से जुड़े एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि एग्रीगेटर्स का एक सेगमेंट दूसरे को सब्सिडी न दे। इसलिए यह टर्नओवर के बजाय ट्रांजैक्शन पर आधारित होना चाहिए। एक अन्य एक्सपर्ट ने कहा कि इस बात पर करीब-करीब आम सहमति है कि सीधे तौर पर उस बिजनेस से जुड़े गिग रेवेन्यू पर चार्ज लगाया जाना चाहिए। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह स्कीम लगभग तैयार है।

चीता संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए वन विभाग ने की व्यापक तैयारियां

चार वन परिक्षेत्रों में वन विभाग का निगरानी अभियान, ट्रैकिंग टीमों को सौंपी जिम्मेदारी

एक सत बुलेटिन, मुरैना



सामान्य वनमण्डल मुरैना अंतर्गत चीता सहित अन्य वन्यप्राणियों के संरक्षण, सुरक्षा एवं सतत निगरानी के लिए वन विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के पालन में वन परिक्षेत्र मुरैना, जौरा, सबलगढ़ एवं पहाड़गढ़ में विशेष निगरानी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत वन अमले द्वारा दिन-रात गश्ती, ट्रैकिंग एवं वनक्षेत्र से लगे ग्रामों में जन-जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। चीता संरक्षण एवं निगरानी की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए वनमण्डलाधिकारी श्री हरिश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को वनमण्डल स्तर पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चीता संरक्षण, सुरक्षा एवं सतत निगरानी के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही चीता निगरानी एवं सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही वनमण्डल स्तर पर मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है। वनक्षेत्र से लगे ग्राम खिरेटा, उसैथ, ऐंती, पढ़ावली, उदुआपुरा, जडेरू, कन्हार, कालाखेत एवं मनोहरपुरा सहित अन्य ग्रामों में वन अमले द्वारा वन समितियों एवं ग्रामीणों को चीते की गतिविधियों तथा संभावित विचरण क्षेत्रों के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों को आवश्यक सावधानियां बरतने, सुरक्षित व्यवहार अपनाने तथा चीते अथवा अन्य वन्यप्राणियों की गतिविधियों की जानकारी तत्काल वन विभाग को देने की समझाइश दी जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर चीता मित्र बनाने की कार्यवाही भी की जा रही है। चीता एवं अन्य वन्यप्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वनमण्डल मुरैना के सभी वन परिक्षेत्रों में विशेष ट्रैकिंग टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें दिन-रात गश्ती कर वनक्षेत्रों में सतत निगरानी रख रही हैं। वनमण्डल मुरैना की ट्रैकिंग टीम एवं कूनो ट्रैकिंग टीम संयुक्त रूप से कार्य करते हुए अवैध शिकार, अवैध गतिविधियों तथा वन्यप्राणियों की सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों पर विशेष नजर रख रही हैं। अभियान के अंतर्गत वनक्षेत्र से लगे खेतों एवं कृषि भूमि का सघन निरीक्षण भी किया जा रहा है। इस दौरान अवैध रूप से लगाए गए करंटयुक्त विद्युत तारों, बाड़, फंदों एवं वन्यप्राणियों के लिए घातक अन्य साधनों की जांच की जा रही है। ग्रामीणों को ऐसे अवैध साधनों का उपयोग नहीं करने तथा अवैध शिकार या वन्यप्राणियों की सुरक्षा से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल वन विभाग को देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा चीता संरक्षण एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मैदानी अमले को निरंतर सक्रिय रखा गया है। चीते की सुरक्षित निगरानी, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वन्यप्राणी हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं और इनके संरक्षण में जनभागीदारी महत्वपूर्ण है। सभी नागरिक वन्यप्राणियों की सुरक्षा में सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल वन विभाग को दें।

प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करेगा नरवाई जागरूकता रथ



एक सत बुलेटिन, मुरैना

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने गुरूवार को जिले में नरवाई प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से नरवाई जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ जिले के नरवाई जलाने की घटनाओं से प्रभावित एवं चिन्हित हॉटस्पॉट ग्रामों में भ्रमण कर किसानों को फसल अवशेष (नरवाई) नहीं जलाने तथा उसके वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए जागरूक करेगा।

जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिले की विभिन्न तहसीलों के चिन्हित ग्रामों में रथ के माध्यम से किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी जाएगी। इनमें तहसील बामौर का जयपुर उर्फ नयागांव, तहसील जौरा के बिसंगपुरा, उमेदगढ़ बंसी, खनेता, सिकरोदा, सुजानगढ़ी, मई, तुंडिला एवं डिडोखारी, तहसील कैलारस के सेमई, स्यावता, बिलगांव क्वारी, नयागांव मानगढ़ एवं शेखपुर तथा तहसील सबलगढ़ के मांगरोल, बत्तोखर, कटघर, कुल्होली, कैमरी, मुरवाई एवं झुंडपुरा ग्राम शामिल हैं। जागरूकता रथ के माध्यम से किसानों को बताया जाएगा कि नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है तथा उसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही वायु प्रदूषण बढ़ने, पर्यावरण संतुलन बिगड़ने तथा जन-धन एवं जैव विविधता को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 6 नवम्बर को मुरैना जिले के ग्राम करुआ में स्वामित्व योजना के हितग्राहियों से करेंगे संवाद



एक सत बुलेटिन, मुरैना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार, 06 नवम्बर 2026 को मुरैना जिले के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम करुआ में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक दिलाने तथा संपत्ति संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है। स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित मकानों एवं अन्य संपत्तियों का सर्वेक्षण कर पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख एवं संपत्ति स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त होने के साथ ही संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा उन्हें आर्थिक गतिविधियों एवं वित्तीय सुविधाओं का लाभ लेने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वामित्व योजना के संबंध में कहा है कि इस धनतेरस पर मध्यप्रदेश में सुख-समृद्धि का नया उजाला आएगा। आगामी 6 नवम्बर को मंत्री, सांसद एवं विधायक गांवों में पहुंचकर अपनी उपस्थिति में शत-प्रतिशत रजिस्ट्री पूर्ण कराएंगे। प्रदेश में अब तक लगभग 15 लाख 98 हजार 46 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं तथा 15 नवम्बर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों का वैधानिक मालिकाना हक दिलाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रातः 11 बजे भोपाल स्थित स्टेट हैंगर से विमान द्वारा ग्वालियर के लिए रवाना होंगे तथा प्रातः 11:45 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12:10 बजे मुरैना हेलीपैड पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मुरैना हेलीपैड से कार द्वारा भाजपा कार्यालय पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके पश्चात दोपहर 1:40 बजे भाजपा कार्यालय से ग्राम करुआ के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम करुआ में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे ग्राम करुआ से कार द्वारा मुरैना हेलीपैड पहुंचेंगे तथा दोपहर 2:35 बजे हेलीकॉप्टर से भिण्ड जिले के लिए रवाना होंगे।

चंबल का डकैत कल्ली गुर्जर मुठभेड़ में गिरफ्तार

मुरैना। मुरैना पुलिस ने गुरुवार को चंबल के डकैत कल्ली गुर्जर को गिरफ्तार किया है। शॉर्ट एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है। बानमौर थाना पुलिस की टीम उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। बताया जा रहा है कि कल्ली पर मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर जिले में कई संगीन मामले दर्ज हैं। इनमें 20 मामले हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और डकैती के हैं। वो सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहा था। इन वीडियो में वह अपने दुश्मनों को धमकी देता नजर आ रहा था। कल्ली पर 80 हजार रुपए का इनाम था। उसे करीब 200 जवानों की टीम तलाश कर रही थी। करीब 20 दिन पहले कल्ली गुर्जर का धमकाते हुए वीडियो सामने आया था। कल्ली मुरैना के महेश्वर मंदिर के सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। वह अपने विरोधी करुआ गुर्जर निवासी जड़ेरुआ को ललकारते हुए कह रहा है कि मैं मंदिर आ गया हूं, दम है तो आकर मिल। इससे पहले करुआ ने वीडियो में कल्ली और उसके परिवार को लेकर अपशब्द कहे थे। इसी के जवाब में कल्ली ने वीडियो जारी कर विरोधी को ललकारा था। डकैत कल्ली गुर्जर ने तीन महीने पहले ग्वालियर के एबी रोड (आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे) पर कंटेनर के चालक से रंगदारी मांगी थी। डकैत अपने साथियों के साथ बिना नंबर की सफेद बोलेरो से आए थे। जब चालक ने इनकार किया तो गाड़ी पर फायरिंग की। गोलियों से कंटेनर के 12 टायर पंक्चर (बर्स्ट) हो गए।

कलेक्टर ने एमजेएस महाविद्यालय का किया निरीक्षण

लगन, मेहनत और ईमानदारी से मिलेगी सफलता : कलेक्टर

एक सत बुलेटिन, भिण्ड



कलेक्टर श्री पवन जैन ने प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, एमजेएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिण्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कॉलेज परिसर का अवलोकन किया और छात्र-छात्राओं के साथ संवाद कर अपने अनुभव साझा किए और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत भिण्ड श्री वीरसिंह चौहान, महाविद्यालय प्राचार्य श्री सुनील त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर विद्यार्थी को अपनी रुचि और स्किल को पहचानना चाहिए और उसी दिशा में लगातार प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में जो भी कार्य किया जाए, उसे मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अच्छी संगत बनाएं और अपने साथियों को भी सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बुराई का रास्ता सरल होता है, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता। इसके विपरीत अच्छाई का रास्ता कठिन जरूर है, परंतु मुश्किलों का साहस से सामना करते हुए मंजिल अवश्य पाई जा सकती है। कलेक्टर श्री जैन ने छात्रों से ज्ञान साझा करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। इसलिए जो पढ़ा जाए, उसे साथियों के साथ बैठकर चर्चा और शेयर करना चाहिए। उन्होंने नशे से दूर रहने तथा अपने साथियों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। इसके बाद कलेक्टर ने प्रोफेसरों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही उनके बीच डिबेट, चर्चा और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वे आत्मविश्वास और खेल भावना के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य शिक्षकों के हाथों में है, इसलिए उन्हें उचित मार्गदर्शन देकर सही राह दिखाना शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। नशे की ओर झुकाव रोकने के लिए छात्रों को लगातार समझाइश दी जाए। कलेक्टर ने महाविद्यालय प्राचार्य को कॉलेज की सफाई, रंगाई-पुताई तथा स्मार्ट क्लासेस निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त परिसर छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाएगा।

दिव्यांगजनों के स्क्रीनिंग एवं शिविरों के प्रति जागरूकता के लिए गांवों और शहरों में किया जा रहा वातावरण निर्माण

एक सत बुलेटिन, मुरैना



जिले के सभी आय वर्ग के दिव्यांगजनों को पुनर्वास एवं शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्टरवार स्क्रीनिंग एवं विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उप संचालक एवं डिप्टी कलेक्टर श्री आर.के. सिन्हा के नेतृत्व में जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) द्वारा यह शिविर 21 अक्टूबर 2026 से 07 जनवरी 2027 तक आयोजित किए जा रहे हैं। शिविरों में जिले के अधिक से अधिक दिव्यांगजनों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा उन्हें शिविरों के उद्देश्य, लाभ एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने के लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में शासकीय कला पथक दल, मुरैना द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वातावरण निर्माण किया जा रहा है। दिनांक 04 एवं 05 नवम्बर 2026 को क्रमशः देवरी, रामरतन का पुरा, गोपालपुरा, हेतमपुर एवं पिपरई में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कला पथक दल के सदस्यों ने गीत-संगीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आमजन को दिव्यांगजनों के लिए आयोजित स्क्रीनिंग एवं यूडीआईडी शिविरों की जानकारी दी तथा पात्र दिव्यांगजनों को शिविरों में पहुंचकर पंजीयन, जांच एवं आवश्यक सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को बताया गया कि इन शिविरों का उद्देश्य दिव्यांगजनों की पहचान, आवश्यक जांच एवं पुनर्वास संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित

मुरैना! मध्यप्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना 2026-27 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मुरैना के सहायक संचालक ने बताया कि योजना के अंतर्गत चयनित मेधावी विद्यार्थियों को शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में स्नातकोत्तर, शोध उपाधि तथा पोस्ट-पीएचडी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के आधिकारिक पोर्टलपर जाकर अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन लॉक कर सकते हैं। प्रोफाइल पंजीयन के लिए समग्र आईडी के साथ डिजिटल जाति, आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र का लिंक होना आवश्यक है। ऑनलाइन फॉर्म लॉक करने के 15 दिनों के भीतर आवेदन का प्रिंटआउट और सभी स्वप्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां आयुक्त कार्यालय, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण में डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जमा करना अनिवार्य है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पूरे वर्ष चालू रहेगी। प्रत्येक 1 माह की अवधि के विभिन्न चरणों में प्राप्त आवेदनों को एकत्र कर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया और साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। आवेदन या तकनीकी दस्तावेजों से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी विभागीय हेल्पलाइन नंबर 0755-2553329, 0755-2675521 पर संपर्क कर सकते हैं।

कलेक्टर ने पराली प्रबंधन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

किसानों को पराली न जलाने एवं फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए करेगा जागरूक

एक सत बुलेटिन, भिण्ड



जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने तथा किसानों को फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आज कलेक्टर श्री पवन जैन ने पराली प्रबंधन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री वीरसिंह चौहान, उप संचालक कृषि श्री राम सुजान शर्मा, कृषि अभियांत्रिकी विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि खेतों में पराली जलाना पर्यावरण, मिट्टी की उर्वरता एवं मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। पराली जलाने से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं, भूमि की जैविक गुणवत्ता प्रभावित होती है तथा वायु प्रदूषण बढ़ता है। इससे आसपास के नागरिकों, बच्चों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जागरूकता रथ जिले के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर किसानों को ऑडियो संदेशों एवं जनसंपर्क के माध्यम से पराली नहीं जलाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों एवं वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी भी प्रदान करेगा। कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की गई है कि धान एवं अन्य फसलों की कटाई के बाद खेतों में पराली अथवा नरवाई में आग बिल्कुल न लगाएं। पराली को खेत में मिलाकर जैविक खाद के रूप में उपयोग करें, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े। स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, मल्चर एवं अन्य कृषि यंत्रों की सहायता से फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करें। पराली को पशु चारे, कम्पोस्ट एवं अन्य उपयोगी कार्यों में लाने का प्रयास करें।

आसपास पराली जलाने की घटना दिखाई देने पर तत्काल संबंधित प्रशासन अथवा कृषि विभाग को सूचना दें। प्रशासन की सख्त चेतावनीः कलेक्टर श्री जैन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत पराली एवं नरवाई जलाना प्रतिबंधित है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं पंचायत विभाग का संयुक्त दल ग्रामीण क्षेत्रों में सतत निगरानी एवं निरीक्षण करेगा। आइए, संकल्प लें–न पराली जलाएंगे, न जलाने देंगे। खेत की मिट्टी बचाएंगे, पर्यावरण स्वच्छ बनाएंगे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर बालाघाट के 100 गांवों का होगा कायाकल्प

नक्सलवाद से मुक्ति के बाद बालाघाट अब लिख रहा विकास की नई इबारत : मोहन

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय को सुरक्षा के साथ विकास का लाभ मिलना ही चाहिए। विकास का प्रकाश समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नक्सलवाद की छाया से मुक्त होने के बाद बालाघाट जिला अब विकास, शिक्षा, रोज़गार और आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर बालाघाट जिले के 100 गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इन दिनों तेजी से काम किया जा रहा है। मिशन आदि सेवा के नाम से चलाये जा रहे इस मिशन के तहत इन गांवों के समग्र विकास के लिए 330 करोड़ रुपये की लागत के 800 से अधिक विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इन लक्षित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका और रोजगार के नए-नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में बालाघाट जिले के कलेक्टर श्री आदित्य सिंह के नेतृत्व में एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। इस कार्ययोजना के तहत अधिकारियों द्वारा अब तक लगभग 70 गांवों का भ्रमण कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया जा चुका है। प्रत्येक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी और सभा मंच विकसित करने की योजना है। इससे बच्चों और युवाओं को डिजिटल शिक्षा तथा सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा और जनजातीय संस्कृति को रोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटन सर्किट और होम स्टे विकसित किए जाएंगे। बैहर विकासखंड के ग्राम लगमा में एक बैगा हाट भी तैयार किया गया है, जहां विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलेगा। वहीं ई-मार्केट प्लेटफॉर्म के जरिए बांस शिल्प, शहद, जैविक उत्पाद, वनोपज और स्व-सहायता समूहों की सामग्री को व्यापक बाजार से जोड़ा जाएगा। दूरस्थ बैगा बहुल गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बैगा आरोग्य एवं पोषण एक्सप्रेस की भी योजना है। युवाओं को शासकीय योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष पोर्टल और विकास कार्यों की निगरानी के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड भी तैयार किया जा रहा है। इन सभी पहलों से नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर आए गांवों में विकास, आत्मनिर्भरता और आर्थिक समृद्धि के नए अवसर सृजित होंगे।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने किया 150 बिस्तरीय अस्पताल निर्माण का निरीक्षण

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**





उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने गुरूवार को सतना जिले के प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय परिसर सतना पहुंचकर वहां चल रहे 150 बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर सांसद सतना श्री गणेश सिंह और महापौर श्री योगेश ताम्रकार भी उनके साथ उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान 150 बिस्तरीय अस्पताल के अब तक किये गये निर्माण कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने पीआईयू के अधिकारियों से कहा कि अस्पताल का कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाये। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल भवन के पूर्ण होने के पहले आवश्यक उपकरण और फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था भी पूर्ण कर ली जाये। कार्यकारी एजेंसी एसडीओ पीआईयू मंदाकिनी गुप्ता ने इस मौके पर बताया कि जिला चिकित्सालय सतना में 100 बिस्तरीय वार्ड और 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लाक और इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ ब्लाक का निर्माण 32.54 करोड की लागत से किया जा रहा है। निविदाकार मेसर्स जाकिर हुसैन रीवा द्वारा 15 अक्टूबर 2025 से कार्य प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में भवन के चतुर्थ तल के छत का कार्य चल रहा है। जबकि ग्राउण्ड एवं प्रथम तल पर प्लास्टर और द्वितीय तल पर ब्रिक वर्क किया जा रहा है। सतना जिला चिकित्सालय परिसर में बन रहे 150 बिस्तरीय नवीन अस्पताल भवन का कार्य मई 2027 तक पूरा कर लिया जायेगा। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला, सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ. सिंह सहित पी.आई.यू. के अधिकारी उपस्थित रहे।

निशातपुरा कारखाने में यूनिकोड मानक फॉन्ट पर हिंदी कार्यशाला आयोजित

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना, निशातपुरा में 04 नवंबर 2026 को 'कंप्यूटर पर यूनिकोड समर्थित मानक फॉन्ट का प्रयोग' विषय पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री प्रफुल्ल वी. कोहाड़े के संरक्षण एवं कार्य प्रबंधक (यांत्रिक) श्री आशीष झारिया की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में 51 रेलकर्मियों ने सहभागिता की। मुख्य वक्ता श्री घनश्याम प्रसाद नामदेव, सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग, जबलपुर ने पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से यूनिकोड की उपयोगिता एवं कंप्यूटर पर इसके व्यावहारिक प्रयोग का प्रशिक्षण दिया। संपर्क राजभाषा अधिकारी श्री संदीप शर्मा ने स्वागत भाषण में दैनिक कार्यालयीन कार्यों में यूनिकोड मंगल फॉन्ट अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर श्री आशीष झारिया ने कहा कि डिजिटल कार्यप्रणाली में हिंदी को अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक है।

पानी की हर बूंद का समुचित उपयोग, जल-सुरक्षित विकसित मध्यप्रदेश ड्रॉफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

वर्ष 2037 तक 50% उपचारित जल के पुनः उपयोग का रखा लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, समृद्ध और पर्यावरणीय दृष्टि से सतत् जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'अर्बन ग्रोथ कॉनक्लेव 2.0' में 'मध्यप्रदेश उपचारित अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग नीति-2026' का प्रारूप सार्वजनिक परामर्श एवं सुझावों के लिए आधिकारिक रूप से जारी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के 'सबका साथ, सबका विकास और सर्वसमावेशी कल्याण' के विज़न पर आधारित यह पॉलिसी ड्रॉफ्ट मध्यप्रदेश के जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के भविष्य को एक नई दिशा और ऊँचाई प्रदान करेगी। भावी शहरी एवं जल आवश्यकताओं के लिए तैयार की गई है 'मध्यप्रदेश उपचारित अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग नीति : 2026' प्रदेश में तीव्र गति से हो रहे नगरीकरण, औद्योगिक विस्तार और जल की बढ़ती मांग के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधनों का सतत् प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। सीवेज उपचार के पश्चात् उपलब्ध जल को अपशिष्ट के स्थान पर उपयोगी संसाधन के रूप में विकसित कर पेयजल एवं भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए यह नीति एक क्रांतिकारी कदम है। 'पानी की हर बूंद का समुचित उपयोग, जल-सुरक्षित विकसित मध्यप्रदेश' के लिए यह नीति न केवल जल संसाधनों पर दबाव कम करेगी।

भोपाल मंडल में सतत खाद्य प्रणाली के प्रति जागरूकता अभियान आयोजित

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल द्वारा बीआरआईसीएस सतत जीवनशैली सप्ताह के अंतर्गत 04 नवंबर 2026 को दिवस-4 की थीम 'सतत खाद्य प्रणाली अपनाना' पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य रेलवे परिसरों में सतत खाद्य प्रणाली एवं जिम्मेदार खाद्य उपभोग को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ भोजन की बर्बादी रोकने और खाद्य संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति यात्रियों, रेलकर्मियों एवं खानपान स्टॉल संचालकों को जागरूक करना रहा। इस अवसर पर रेलवे स्टेशनों के डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से सतत खाद्य उपभोग एवं भोजन की बर्बादी रोकने संबंधी जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए। इसके अतिरिक्त खानपान क्षेत्रों एवं फूड स्टॉल के निकट जागरूकता पोस्टर लगाए गए तथा जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को जिम्मेदार खाद्य उपभोग का संदेश दिया गया।

जीएम दिलीप कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुआ ग्रैंड कैंपफायर समारोह

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



पश्चिम मध्य रेल भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की 9वीं राज्य स्तरीय रैली का भव्य ग्रैंड कैंपफायर एवं समापन समारोह 04 नवंबर को रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड, हबीबगंज रेलवे कॉलोनी, भोपाल में उत्साह, उमंग एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री दिलीप कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक भोपाल श्री पंकज त्यागी, वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक श्री नीरज कुमार सहित पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय एवं भोपाल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय रैली में पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय सहित भोपाल, जबलपुर एवं कोटा मंडलों से लगभग 400 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स एवं यूनिट लीडर्स ने सहभागिता की। रैली का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मनिर्भरता, सेवा भावना, टीमवर्क, रचनात्मकता एवं राष्ट्रप्रेम की भावना को प्रोत्साहित करना है। समारोह का शुभारंभ ध्वजारोहण, मार्च पास्ट एवं बैंड डिस्प्ले के साथ हुआ। विभिन्न मंडलों से आए स्काउट्स एवं गाइड्स के दलों ने अनुशासित मार्च पास्ट एवं आकर्षक बैंड प्रदर्शन के माध्यम से अपनी संगठनात्मक क्षमता, एकजुटता एवं अनुशासन का परिचय दिया। इसके पश्चात ग्रैंड कैंपफायर समारोह में मुख्य अतिथि महाप्रबंधक श्री दिलीप कुमार सिंह को जनरल सैल्यूट दिया गया तथा शिविर का निरीक्षण कराया गया। ग्रैंड कैंपफायर के दौरान प्रतिभागियों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। विभिन्न मंडलों के स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा प्रस्तुत लोकनृत्य, समूह गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित अतिथियों एवं दर्शकों का मन मोह लिया। इन प्रस्तुतियों में देश की सांस्कृतिक विविधता, लोक परंपराओं एवं राष्ट्रीय एकता की सुंदर झलक देखने को मिली। इस अवसर पर राज्य स्तरीय स्काउट्स एवं गाइड्स पुरस्कारों के प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कारों का वितरण भी किया गया। विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस राज्य स्तरीय रैली में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण गतिविधियों ने प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा नई दक्षताएं सीखने का अवसर प्रदान किया।

रेलवे ट्रैक एवं विद्युत लाइनों के आसपास अनधिकृत प्रवेश और कार्य करने पर प्रतिबंध

भोपाल। पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल द्वारा रेल विद्युतीकरण कार्य के अंतर्गत बीना-रुठियाई रेलखंड के पगारा से रूठियाई हिस्सों में 25,000 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसी ओवरहेड विद्युत लाइन को दिनांक 05 नवंबर 2026 से ऊर्जीकृत (चालू) किया जा रहा है। पगारा से रूठियाई रेलखंड की ओवरहेड विद्युत लाइन हर समय चालू मानी जाएगी। इस विद्युत लाइन में अत्यधिक उच्च वोल्टेज प्रवाहित होगा, जिससे संपर्क में आने अथवा नजदीक जाने पर जानलेवा दुर्घटना हो सकती है। बीना-रुठियाई रेलखंड पर पगारा से रूठियाई 25 हजार वोल्ट की ओवरहेड विद्युत लाइन 05 नवंबर से चालू अतः सभी रेल उपयोगकर्ताओं, आम नागरिकों एवं संबंधित क्षेत्र के निवासियों से अपील है कि वे विद्युत लाइन के समीप न जाएं, उसके नीचे किसी प्रकार का कार्य न करें तथा रेलवे ट्रैक एवं परिसर में अनधिकृत प्रवेश से बचें। रेलवे प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि अपनी सुरक्षा के लिए विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।

पक्षियों की पहचान और प्रकृति संरक्षण के प्रति छात्राओं को किया जागरूक

सरोजिनी नायडू महाविद्यालय में विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पक्षी अवलोकन पर विशेष व्याख्यान

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, शिवाजी नगर में 4 नवंबर 2026 को प्राणीशास्त्र विभाग द्वारा विश्व प्रकृति निधि (वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर–डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के सहयोग से पक्षी अवलोकन विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को पक्षियों की विविधता, उनकी पहचान, पर्यावरण में उनकी भूमिका तथा प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. प्रतिमा यादव ने की। उन्होंने छात्राओं को प्रकृति से जुड़ने और उसके सान्निध्य में आनंद तलाशने का संदेश देते हुए कहा कि प्रकृति के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने छात्राओं को अपने आसपास के प्राकृतिक परिवेश को समझने और जैव विविधता के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विश्व प्रकृति निधि की मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य संचालक डॉ. स्वाति मोघे रहीं। उन्होंने प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में पक्षियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पक्षी पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी उपस्थिति प्राकृतिक संतुलन और जैव विविधता की समृद्धि का संकेत देती है। मुख्य वक्ता विश्व प्रकृति निधि के शिक्षा अधिकारी डॉ. अभय राय ने छात्राओं को पक्षियों की पहचान के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने पक्षियों की शारीरिक बनावट, रंग, आवाज और व्यवहार के आधार पर उनकी पहचान करने की विधियों को समझाया। साथ ही पक्षी अवलोकन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, पक्षियों से उचित दूरी बनाए रखने तथा उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान न पहुंचाने के महत्व पर भी जानकारी दी। इस अवसर पर विश्व प्रकृति निधि द्वारा संचालित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और छात्राओं के लिए उपलब्ध इंटर्नशिप के अवसरों की जानकारी भी साझा की गई, ताकि छात्राएं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्रशासनिक अधिकारी डॉ. छाया चंद्रवंशी, प्राणीशास्त्र विभाग के समस्त सदस्य तथा बीएससी एवं एमएससी की छात्राएं उपस्थित रहीं।

एमएसएमई मंत्री श्री काश्यप और मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने निर्यातकों के लिए पाँच व्यवस्थाओं का किया शुभारंभ

व्यापार बढ़ाने के लिए नीति में बदलाव की आवश्यकता होगी तो वह भी करेंगे: मंत्री काश्यप

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**



भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सहयोग से गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटरमें मध्यप्रदेश एक्सपोर्ट एंड एफटीए कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग और म.प्र. औद्योगिक विकास निगम ने विदेश व्यापार महानिदेशालय और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के साथ मिलकर कॉन्क्लेव आयोजित की। कॉन्क्लेव में प्रदेश के 800 से अधिक निर्यातकों और उद्यमियों ने सहभागिता की। कॉन्क्लेव में तकनीकी सत्र, उद्घाटन सत्र, तीन पैनल चर्चाएँ, दो प्रेजेंटेशन और समापन पर फायरसाइड चर्चा हुई। परिसर में 7 शासकीय संस्थाओं के और प्रदेश के ओडीओपी एवं जीआई उत्पादों के 14 स्टॉल लगाए गए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि देश के कुल निर्यात में लगभग आधा हिस्सा एमएसएमई का है। चीन में बिजली, श्रम और अधोसंरचना की लागत बढ़ने से भारत और मध्यप्रदेश के निर्माताओं के लिए विश्व बाजार में बड़ा अवसर बना है, और इसका लाभ लेने के लिए उद्यमी उत्पादन का पैमाना और क्षमता बढ़ाएँ, जिससे प्रति इकाई लागत घटे। उन्होंने कहा कि यूके और यूरोपीय संघ के साथ समझौतों में परिधान पर जीरो शुल्क के लिए उत्पाद में भारतीय अंश अधिक होना आवश्यक है, और पीएम मित्र पार्क में फाइबर से कताई और बुनाई तक का पूरा काम होने से प्रदेश के परिधान निर्यातकों को इसका लाभ मिलेगा। मंत्री श्री काश्यप ने उद्योग संगठनों से कहा कि वे हर उद्योग की निर्यात संभावनाएँ खोजकर शासन के पास लाएँ, और आश्वासन दिया कि छोटे या बड़े किसी भी उद्योग का व्यापार बढ़ाने के लिए नीति में बदलाव की आवश्यकता होगी, तो राज्य शासन वह भी करेगा। मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल ने उद्योग को व्यापार समझौतों का लाभ लेने के गुर बताए। उन्होंने कहा कि सरकार समझौते से बाजार का रास्ता खोलती है, खरीददार तक पहुँचना गुणवत्ता और कीमत से तय होता है, और समझौता निर्यातक को प्रतिस्पर्धी से आगे निकलने की अतिरिक्त बढ़त देता है। उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के लिए उद्योग संगठनों को तीन कदम बताए: पहला, अपने क्षेत्र के कम से कम पाँच ऐसे उत्पाद चुनें जिनमें निर्यात की सबसे अधिक क्षमता है; दूसरा, इन उत्पादों के लिए एफटीए साझेदार देशों में सबसे संभावनाशील बाजार पहचानें; तीसरा, उन इकाइयों को चिन्हित करें जो इस स्तर तक निर्यात कर सकती हैं। मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने कहा कि उद्योग और शासन मिलकर काम करें, तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा तय 1 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य एक वर्ष में प्राप्त किया जा सकता है। फार्मा उद्योग की समस्या पर उन्होंने जानकारी दी कि निर्यात आदेश मिलने पर औषधि लाइसेंस में उत्पाद जोड़ने की स्वीकृति में अब दो दिन से अधिक नहीं लगेंगे, और म.प्र. औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक को उद्योग संगठनों के साथ नियमित संवाद मंच बनाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री काश्यप और मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने कॉन्क्लेव में निर्यातकों के लिए पाँच व्यवस्थाओं का शुभारंभ किया। मध्यप्रदेश एफटीए कार्य योजना 2026-27 में सात उद्देश्यों के अंतर्गत 31 कार्य बिंदु हैं। निर्यातकों के लिए एफटीए हैंडबुक में हर उत्पाद के लिए समझौते का लाभ, उत्पत्ति का नियम और संपर्क की जानकारी है। एफटीए हेल्पडेस्क के फोन नम्बर 0755-2577145 पर और निर्यातक प्रश्न पूछ सकते हैं।

स्वामी **एक सत प्रयास जनकल्याण समिति** के लिए मुद्रक प्रकाशक एवं **सम्पादक अमित शर्मा** द्वारा 401, जीवन छाया अपार्टमेंट, राइट टाउन, जबलपुर (मप्र) पिन: 482004 से प्रकाशित एवं पीजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई, जबलपुर, मध्य प्रदेश 482002 से मुद्रित। पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI-MPHIN/2019/78787, स्थानीय संपादक: विक्रम सिंह। E-mail:eksatbulletin@gmail.com, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु हेड ऑफिस संपर्क करें– ए-1 माचना कॉलोनी, शा.राजीव गांधी हाई स्कूल शिवाजी नगर 6 नंबर बस स्टाप पास भोपाल। फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9893311784